Haryana Vidhan Sabha

Debates

13th June, 1967

Vol. 1-No. 15

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 13th June, 1967

	Page
Starred Questions and Answers	1
Unstarred Question and Answer	14
Question of Privilege	15
Call Attention Notice	15
Second Report of the Business Advisory Committee	
Statement by-	
(i) The Minister for Irrigation and	
Power in regard to Call Attention	
Notice No. 12	17
(ii) The Minister of State for Rural Electrification	
in regard to Call Attention notice No. 15	17
Papers Laid on the Table	20
General Discussion on the Budget for	
The year 1967-68	20-68

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh.

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, No. 15

DATED THE 13TH JUNE, 1967

Read	For	Page	Line
बतायेंगे	बतायेंग	(15) 1	20
मुकर्रर	मर्कर	(15) 1	21
फैसला	फसला	(15) 1	26
बारे	बारे	(15) 2	4
बतायेंगे	बतायगे	(15) 3	First
लेकर	लकर	(15) 4	11
बनता	बनाता	(15) 5	12
चीनी	चानी	(15) 5	12
जी	जो	(15) 5	19
State	Sate	(15) 6 18	(from below)
Any	Ny	(15) 7	Last line

200	00	(15) 8	6
Form	From	(15) 8	12
Jagadhri	Jagadhari	(15) 10	3,18
देहली से	देहला से	(15) 11	11
REPORT	REORT	(15) 16	1
Free	Fre	(15) 19	6 (From below)
और	और	(15) 25	5
पुलिटीकल	पुलिटाकल	(15) 25	10
शे	श	(15) 26	4
नीचे	नाचे	(15) 26	7
सी	सा	(15) 26	8
बोझ	बाझ	(15) 26	10
कोई	काई	(15) 28	19
Industries we	Induries were	(15) 32	3
State	State	(15) 32	11

Budget	Bugt	(15) 32	22,27
लग जाए	लग मर जाए	(15) 32	42
Contrary	Conrary	(15) 35	38
Lieu of	Lieu of of	(15) 36	36
Grains	Lrains	(15) 37	2 (From below)
मेम्बरान	मेबरान	(15) 42	27
प्रोपोजल	प्रापोजल	(15) 47	2 (From below)
सैकेटरीज	सैकेट्रीज	(15) 48	14
रिप्रेजेंटेटिव	प्रेजैंटेटिव	(15) 49	30
गवर्नमैंट	गर्वमैंट	(15) 50	2 (From below)
शैडयूल्ड	शोडूल्ड	(15) 51	8
रजिस्ट्रेशन	रजिसट्रशन	(15) 57	25
Delete the word	प्राप्त होगी	(15) 57	26
ट्यूबवैल्ज	टयूबवल्ज	(15) 57	33

प्रोवाइड	प्रावाइड	(15) 59	1
पुलिटीकल	पालिटिकल	(15) 59	19

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday the 13th June1967

The Vidhan Sabha met in the Hall of Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 P.M. of the clock. Mr. Speaker (Chaudhri Sri Chand) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Pending Civil Cases

*130. Shri Daya Krishan: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The total number of civil cases which were pending in the civil courts on Ist April 1967 in the State and the number there of which are more than one year old; and

(b) The number of six months old civil appeals which were pending on 1st April 1967?

Shri Mool Chand Jain (Finance Minister) : (a) and (b). The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्री दया कृष्णः क्या वजीर साहिब यह फरमायेंगे कि सिविल कोर्टस के लिये कोइ हिदायत दी गई है कि वे एक साल के अन्दर अपने मुकदमात का फैसला करें?

वित्त मंत्रीः इस के लिए नाटिस चाहिए।

श्री दया कृष्णः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हाई कोर्ट के लिये भी को मियाद मकरूर की गई है ि कवे इस अर्से के अन्दर अपने मुकदमात का फैसला देंगे?

वित्त मंत्रीः स्पीकर साहिब, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री अध्यक्षः जब जवाब नहीं दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। उन्होने तो कहा कि नोटिस चाहिए। आप नोटिस दे, अगली दफा जवाब आ जाऐगा।

श्री दया कृष्णः क्यया मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो एक साल के अन्दर फैसला देने की बात है इस से जल्दी भी वे फैसला दिलाने का इन्तजाम कराएंगे?

Mr. Speaker: This is a suggestion for action.

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहिब यह तो इस सवाल से ही सम्बंध रखता है क्योकि जल्दी जल्दी फैसला न होने से बड़ी दिक्कत होती है कभी मुद्दई मर जाता है तो कभी मुद्दायलै मर जाता हैं।

Mr. Speaker: I absolutely agree with the hon. Member, but you see I cannot compel him to give reply.

Shri Daya Krishan: Then, Sir let the Finance Minister give a reply as to what remedy he would adopt to sove this problem?

वित मंत्रीः यह तो स्पीकर साहिब इस सवाल से सम्बन्धित नहीं क्योंकि इस में हाई कोर्ट जिक्र नहीं हैं। इस में तो सिविल कोर्टस के बारे में पूछा था।

Pending Cases for investigation at Police Station

***131. Shri Daya Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state

(a) The number of ases pending investigation at the various police Stations in the State as on Ist April 1967 amd which are six months old:

(b) the main causes of delay in not putting up the said challans earlier in the respective courts;

(c) the period within which the challans of the said cases are likely to be put up in the courts;

(d) whether some "murties" were recovered from a pond which were recently removed form the Shiv Temple at Jind: if so, whether the police has been able to find out the culprits so far?

Rao Birendra Singh: (a) 238 cases are pending investigation at various Polie Stations in the State as on Ist April 1967 amd are six months old.

(b) Main causes of delay in not putting up the said challans earlier in the respective courts are-

Non-receipt of reports form the Chemical examiner or the hand writing Exerts;

I. Non-receipt of sanction for prosecution form the competent authority;

II. Transfer of P.Ws' to other places;

III. Investigation in some cases bring lengthy and complicated since the same have inter-State links;

IV. Difficulty in obtaining the original record from various officer;

V. Non-availability of the accused who are under-trial in other districts.

VI. Very shortly-within about a month or so

(d) Neither the "murties" which were recently removed form the Shiv Temple at Jind have been recovered do far nor have any culprits been traced.

श्री दया कृष्ण: क्या चीफ मिनिस्टर साहि बतायेगे कि पैस (डी) में जा मुकदमात उन्होनें बताए वे कब रजिस्टर्ड हुए थे? यदि काफी देर पहले हुए थे तो इनकी तफतीश मे क्यों डिले हो रही है?

श्री अध्यक्षः यह तो इस से सम्बन्धित नहीं।

श्री दया कृष्णः अगर यह बात चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाई जाए कि डी.आई. जी. एस. पी. चौधरी दलीप सिंह अैर मेरे रूबरू ये मूर्तियां बरामद हूई है तो क्या वे इस गलत जवाब के मुताल्लिक कोई एक्शन लेंगे?

मुख्य मंत्रीः जरूर लिया जाएगा।

श्री दल सिंहः क्या चीफ मिनिस्टर साहिब ऐक्शन लेने की एश्योंरेंस देंगे यदि जो मूर्तियां नहीं मिली है अगर उनकी जगह बता दी जाएं?

मुख्य मंत्रीः जरूर, जरूर

श्री श्री कृष्णः क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि कितने दिन तक कार्यवाही की जाएगी?

मुख्य मंत्रीः वह तो पहले इतलाह दें। उनसे पूछिए कि कबब इत्तलाह देंगे। मैं ता उसके बाद ही कार्यवाही करूंगा।

Bhiwani City as an Industrial Area

***191. Shri Bhagwan Dev Prabhaker:** Will te Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government to declare Bhiwani city as an industrial area; if so, the details thereof?

Rao Birendra Singh: No; does not arise.

श्री भगवान देव प्रभाकरः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको पता है कि भिवानी तहसील के 75 प्रतिशत लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप इतना लम्बा प्रशन कर देते है कि उस में वक्त बहूत ज्यादा लगता है।

श्री भगवान देव प्रभाकरः कृषि के ऊपर बोझ हलका करने का एक मात्र उपाय यह रहजाता है कि वहां काटिज और बिग इण्डस्ट्रीज लगाई जाएं। तो क्या निकट भविष्य में वहां की खस्ताहाली की बात को ध्यान में रखतें हुए इस पर मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे।

मुख्य मंत्रीः आनरेबल मेम्बर की सजैशन नोट कर ली है गौर करेगें।

Number of Fari price Depots in the State

***175. Shri Ran Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether all the Fair price Depots opned during the lean months of the year 1966-67 in the State are still continuing or their numberhas since been decreased and the reasons therefore?

Major Amir Singh (Minister of State for Rural Electrification): Yes, Still continuing.

श्री रण सिंहः क्या आनरेबल मिनिस्टर बतायेंगे कि जा फेयर प्राईस शाप्स 1966–67 के लीन मंथस में चल रही थी उनमें क्या उसी मात्रा में राशन तकसीम होता है?

राज्य मंत्रीः इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रण सिंहः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर उसी मिकदार में राशन सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : उन्होने जवाब नहीं दिय। वह तो कहते है कि उन्हे टाईम चाहिए यह मालूम करने के लिये।

श्री रण सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि सवाल से सप्लीमेंटरी क्वैश्चन एराईज होता था कि राशन तकसीम होता है या नहीं। जब ऐसी बात थी तो क्या यह मिनिस्टर साहिब का फर्ज नहीं कि वह तैयार होकर आते?

श्री अध्यक्षः यह ठीक बात है लेकिन श्री रण सिंह जी वह टाईम मांग रहे है। कुछ टाईम लेकर वह जवाब देंगे। क्या करूं मै उन्हे मजबूर नहीं कर सकता।

Starred Question No. 230

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of starred Question No. 230. It is therefore, postpond.

Allotment of sugar Quotas

***231. Chaudhri Nasib Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is fact that during the last three months no sugar quotas have been supplied to the rural areas in the State;

(b) Whether it is also a fact that the urban areas in the State have been receiving their sugar quotas regularly;

(c) If the reply to part (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons for discrimination between lthe rural and t;he urban areas in the State;

(d) Hether it is further a fact that the applicants for sugar, maida, suji and ghee for marriages have to get their applications attested by a Patwar, Sarpanch ans a Gazetted Officer and then by the oath Commissioner?

Major Amir Singh (Minister of State for Rural Electrification):

(a) No.

(b) Yes.

(c) Question does not arise.

(d) Yes.

श्री भगवान देव प्रभाकरः स्पीकर साहिब, मंत्री माहेदय ने अभी फरमाया है कि शहरी क्षेत्र में चीनी को कोटा नियमित रूप सप्लाई किया जा रहा है, किन्तु तथ्य यह है कि पिछले महीने हिसार में भिवानी के अन्दर.....

श्री अध्यक्षः प्रभाकर जी आप सवाल पूछें तो बड़ी अच्छी बात है परन्तु उसके साथ आप जो टिप्पणी करते है उससे आपका सताल नहीं रहता । वह तो एक बड़ी लम्बी चौड़ी इंट्रोडक्शन हो जाती है।

श्री भगवान देव प्रभाकरः तो मै, स्पीकर साहिब, निवेदन कर रहा था कि भिवानी में और हिसार के अन्दर पिछले महीने चीनी का कोटा जो निश्यित हुआ था वह नहीं मिला।

श्री अध्यक्षः यह तो आप इनफरमेशन दे रहे है।

श्री भगवान देव प्रभाकरः नहीं, स्पीकर साहिब, मैं ले रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि क्या यह फैक्ट है कि चीनी नही मिली?

श्री अध्यक्षः हां, यो पूछिए।

राज्य मंत्रीः स्पीकर साहिब, ज्वायंट पंजाब के अन्दर 17,550 टन चीनी का कोटा तमाम एरिया के लिये था और इसमें से पोपूलेशन के आधार पर हरियाणा का शेयर 6612 टन बनाता था लेकिन एक्चुअली हमको 6560 अन का कोटा दिया गय।

अक्टूबर 1966 तक हरियाणा के रूरल एरिया ने 800 टन औसत माहबार चीनी उठाई उस कोर्ट के अगैन्सट जो 6000 टन का ज्वायंट पंजाब में रूरल एरिया के लिए था। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने पैटर्न आफ कनजम्पशन के आधार पर हमारा कोटा 1560 टन घटा कर 5000 टन तक मुकर्रर कर दिया। अप्रैल में 28 प्रतिशत का कट और आ गया जिससे हमारा कोटा 3600 टन रहा गया। जून के अन्दर 17 प्रतिशत का दूसरा और कट आ गया और हमारा कोटा 3008 टन हो गया। इसके हिसाब से कोटा जो था रूरल और अरबन एरिया के अन्दर कमती होता गया और यह कुदरती बात थी कि चीनी जो शहरों में चार किलोग्राम मिलती थी वह आठ सौ ग्राम पर आ गई।

श्री भगवान देव प्रभाकरः स्पीकर साहिब, मेरे कवैश्चन का पता ही नहीं लगा। मैने तो पूछा था कि क्या पिछले महीने भिवानी और हिसार मैं चीनी मिली?

राज्य मंत्रीः मेरे नोटिस के मुताबिक तो मिली है। यादि न मिल हो तो शास्त्री जो बता दें मै उसको जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा।

श्री श्री कृष्णः वैसे तो चीनी मिलती नहीं, लेकिन ब्लैक में क्यों ज्यादा मिलती है।

राज्य मंत्रीः पकडवा दे अगर आपको मालूम है। सख्त कार्रवाई करेंगे।

श्री दया कृष्णः हजारों मन ब्लैक में बिक्री है और अब भी बिक रही हैं।

मुख्य मंत्रीः आपके जमाने में बिकी है।

चौधरी रिजक रामः इसकी क्या वजह है कि अगर सप्लाई में कमी हो गई तो देहात में इसके पेशेंजर कोटा कम कर दिया गया या बंद कर दिया और शहर में बदस्तूर है।

राज्य मंत्रीः डिप्टी कमिशनर्ज का आर्डर दिया गया है कि मैरिजिज की जरूरत पूरी करने के लिये फिलहाल कोटा डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि मैरिज में चीनी दी जा सकें।

चौधरी रिजक रामः डाइवर्ट करने का क्या मतलब है कि चीनी का राशन मिलेगा ही नहीं?

राज्य मंत्रीः मैरिजिज का सीजन निकल जाने के बाद मिलेगा।

चौधरी रिजक रामः कितना कोटा मुकर्रर दिया गया देहात के लिये?

राज्य मंत्रीः 100 ग्राम।

श्री रण सिंहः क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि कोटा डाइवर्ट करने के बावजूद भी शादियों की तारीखें निकल गई और उनको चीनी नहीं मिल पाई?

राज्य मंत्रीः हां, कुछ अनसोशल एलीमेंट रूकावट डालता है उसको राउंड अप करने की कोशिश की जा रही है।

श्रीमती लेखवती जैनः क्या फस्ट जुलाई से कोटा मिलने लगेगा?

राज्य मंत्रीः हमारी यही कोशिश होगी।

श्रीमती लेखवती जैनः देहात में शादियों के लिये क्या कोटा डाइवर्ट नहीं किया गया? वहां क्या आदमी नहीं रहते?

राज्य मंत्रीः मैं तो मानता हूं कि आदमी और आदमी के दरम्यान अन्तर नही होना चाहिए। मगर यह तो पिछली सरकार से पूछिए।

Shortage of sugar in the State

***255. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state-

a) Whether any complaint regarding the shortage of sugar in the Haryana State has recently been received; if not, the reasons for issuing reduced quota of sugr at the depots;

b) Whether any steps are being taken by the Government to meet the shortage referred to in part (a) above; if so, the details thereof?

Major Amir Singh (Minister of state for Rural Electrification):

a) Yes, the reason for such complaints being the reducetion of 3552 tonnes by the Government of India in the State monthly quota of sugar.

b) Yes.

i. The Government of India were approached for restoration of the cut in the monthly quota of sugar for the State and also for making an additional ad hoc allocation of 1000 tonnes for meeting the increased demand of sugar for marriages, but they have not agreed to do so in view of shortfall in the production of sugar in the country this year. The Government of India were again requested to reconsider the matter and incresase our quota of sugar suitably; but they had again turned down this proposal.

ii. Uttar Pradesh Government were requested to permit import of 5000 tonnes khandsari from Uttar Pradesh into Haryana to supplement the available supplies of sugar. They have expressed their inability to spare any khnadsari due to extremely tight supply position of sugar and high prices of khandsari in Uttar Pradesh State.

श्री मंगल सेनः क्या राज्य मंत्री महोदय बतलाएंगे कि भारत सरकार ने हमारा शूगर का कोटान नहीं दिया तो क्या उसने यह इस लिये किया है कि यहां पर संयुक्त दल की सरकार है और कांग्रेस की सरकार नहीं है?

राज्य मंत्रीः यह हम क्या कह सकते है, आप खुद ही अन्दाजा लगा लो।

श्रीमती लेखवती जैनः पहले जवाब में यह कहा गया था कि दिल्ली की सरकार पर सप्लाई डिपेंड करती हैं तो मै पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की सरकार क्या यह भी लिखती है कि इतना देहात में और इतना शहर मैं या कि यह सरकार खुद ही करती है ऐसा?

मुख्य मंत्रीः यह डांटती क्यों है?

श्रीमती लेखवती जैनः जब कसूर अपना हो और चार्ज दिल्ली की गवर्नमैंट पर लगाए तो गुस्सा आएगा ही।

श्री श्री कृष्णः बताया गया कि 100 ग्राम कोटा नियुक्त किया गया, तो मै पूछना चाहता हूं कि इतने कोटे मे ही यह वजीर साहिबान भी गुजारा करते है?

मुख्य मंत्रीः हमारी वजारत में काई ब्राहमण है ही नहीं जो मीठा खाता हो।

Change in the Existing Depot System in the State

***256. Shri Mangal Seing:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government propose to change the existing deports distributing the foodgrains and sugar in the state: if so, the manner in which the Government propose to get the foodgrains and other ontrolled commodities distributed to the public?

Maor Amir Singh (Minister of State for Rural Electrification): Yes. A cop of the notice issued to the public containing details of the new scheme is placed on the table of the House.

Notice

Applications are invited upto 30 June, 1967 for appointment at authorized Fair-Price Depot holeders for the sale of foodgrains and sugar etc. in all towns in district. The applicants must possess for this purpose, on the dat of application a shop duly approved as such by the Municipal Committee/Notified Area Commit tee of the town concerned.

2. Persons who had an interest in a depot at any time in the past and against whom action had been taken or was pending on 1st June 1967 for irregularities allegedly committed by them in the distribution of controlled commodities, viz sugar, atta, rice etc. will not be eligible for appointment as authorized retail depot-holders.

3. All application must be accompanied by an affidavit of the applicat stating clearly that at no time was a depot either in his own name or that of any of his dependents wherein he had any interest whatsoever, cancelled or suspended for any irregularities committed by him his relation and that he had never been prosecuted, convicted for any act of black-marketing or any other mal-practices in the distribution of controlled commodities. The affidavit would also state that no other application for the allotment of a ddepot has been made or will be made by any party in which he or any of his dependents have any financial interest.

4. The persons approved as prospective depot-holders will be permitted to register Distribution Cards of consumers establishments upto 500 cards each. This will be the maximum number of cards to be registered by any prospective depot-holder.

5. The minimum number of cards that a prospective depot-hoder must register for appointment as an authorized retail depot-holder must register for appointemtn as an authorized retail depot hoder is 00 . Such prospective depot holders as will not be able to register the required minimum number of 200 cards by the 30th June 1967 will not be appointed authorized retail depot holders. The cards registered by them will be distributed amongst such authorized retail depot-holders a have registered more than 200 cards but less than 500 cards each.

6. All existing depot-holders are also required to apply a fresh in the prescribed application from like all other applicants, if they want to be considered for appointment as depot-holders under the new scheme. They will be governed like others by the above conditions. If any existing depot-holder under the new scheme. The cards registered by him wilbe distributed among other authorized depot-holders.

7. All persons finally selected for appointment as authorized retail depot holders will be required to enter into an agreement with the District Food and Supplies Controller/District Food and Supplies Officer—on behalf of Governor of Haryana in the prescribed form and to deposit a sum of Rs. 200 as security with District Food and Supplies Officer—within the period specified by the undersigned.

8. The persons appointed as authoriesed retail depot-holders will abide by all the instructions and directions issued from time to time by the District Magistrate, the Distr ict Food and supplies Controller, the District Food and Supplies Officer or any other person acting on their behalf. Their depots are likely to be cancelled and security for feited for their indulging in any irregularities or for breach of an such directions or of the terms of the agreement entered into by them with District Food and supplies Controller/District Food and Supplies Officer besides any other action that may be taken against them under the law.

9. No authorized retail, depot-holder under the new scheme will be allowed t o keep for sale any foodgrains/ wheat/ rice/bajara/ gram/barley and Sugar etc. other than

what may be issued to him by the Food and Supplies Department for distribution as depot.

10. Application alongwith affidavit must be submitted in the prescribed form alongwith a blank agreement form. Sets containing all the three are available generally for sale at----. The exact places where the sets containing application forms etc. are available for sale in your town can be enquired from the Officer of Assistant Food and Supply Officer or Inspector, Food and Supplies.

Dated-------

District Food and Supplies Controller

District Food and Supplies Officer

----------District

Starred Question NO. 193

Mr. Speaker: Extention has been asked for in respect of Starred Question No. 193. It is therefore, postponed.

श्री राम प्रकाशः स्पीकर साहिब, क्या इसी सैशन में ही इस का जवाब आ जाएगा।

Mr. Speakr: I would request the hon. Minister concernedto reply this question during the current session.

श्री रण सिंहः स्पीकर साहिब, पांच तारीख को मेरा एक क्वैस्चन पोस्टपोन हुआ था। क्या मै उम्मी द रखूं कि उस का जवाब इसी सैशन में मुझे मिल जाऐगा?

Mr. Speaker: If you kindly write to me in this connection, I will request the Minister concerned to reply.

Revision of Pay scales of Governemtn Ecployees

***192. Shri Bhagwan Dev Parbhaker:** Will the ministr for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to revise the pay scales of Class III and Class IV Government employees in the State; if so, the date from which and the extent to which the pay scales are proposed to be enhanced?

Shri Mool Chand Jain: A Pay Revision Commit tee has since been set up by the Government to go into the question of revision of pay scales of the State Services as a whle. The Committee would consider the question of revision of pay scales of Class III and Class IV emloyees as well.

Starred Question No. 229

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of Starred Question No. 229. It is therefore postponed.

Lease of Forest Land

***270. Shri Ram Parkash:** Will the Minister for Development be pleased to state-

(a) The total area of land belonging to the Forest Department which has been leased out to the tenants in the State thesilwise;

(b) Whether Government intend to eject the saild lesses; if so, whether they would be given any land in lieu there of?

Shri Partap Singh Daulta:

(a) Tehsil Kaithal	155 acres.
Tehsil Jagadhari	26 acres
Total	**181 acres**

(b) (i) No. Not before the expiry of the lease period.

(ii) Question does not arise.

श्री राम प्रकाशः स्पीकर साहिब, तहसील कैथल में वजीर साहिब ने 155 एकड़ जमीन बताई है जो टैनेंट्स के पास है

और तहसील जगाधरी में सिर्फ 26 एकड़ बताई है जबकि वहां पर एक्युअली 126 एकड़ है। तो उन्होने इन्फर्मेशन को छिपाने की कोशिश की है।

मंत्री: मेरी इत्तलाह तो यही है जो मै ने अर्ज की है।

Lease of Forest Land in Villages Balachaur and Dadupur Chhawni Tehsil Jagadhri

***271. Shri Ram Parkesh:** Will the Minister for Development be pleased to state-

(a) Whether any land belonging to the Forest Department in the villages Balachaur and Dadupur Chhauni, tehsil Jagadhari is held on lease at present by any tenants; if sosince when;

(b) Whether Governemtn intend to withdraw the Said land from the said lessees; is so the reasons therefore?

Shri Partap Singh Daulta:

(a) First part -------- No.

Second part----------Question does not arise.

(b) Question does not arise.

श्री राम प्रकाश: यह इन्फर्मेशन भी गलत दे रहे है। क्या मिनिस्टर साहिब मौके पर जा कर वेरोफाई करने को तैयार होंगे?

Smailipox Cases

***129. Shr Daya Krishan:** Will the Minister for Health be Pleased to state the number of smallpox cases which came to the notice of Government during the period from 1st November 1966 to 31st March 1967 in the State; and the number of deaths occurred as a result thereof?

Shri Sheryo Nath: 2643 cases, resulting in 388 deaths.

श्री दया कृष्ण: मंत्री महोदय ने बताया है कि 2643 केसिज चेचक के हुए और 388 मौते हूई। मै पूछना चाहता हूं कि जिन अफसरों ने रोकथाम नहीं की इस बीमारी को रोकने के लिये उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है?

मंत्री: रोकथाम में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुदरत के कामों को कोई नहीं रोक सकता। शायद दया कृष्ण जी भी न रोक सकतें हो।

श्री पोहलू उपनाम जगजीत सिंह: क्या तजीर साहिब बताएंगे कि चेचक की बीमारी को रोकने के लिये सरकार ने कुछ नए इकदामात उठाए है?

मंत्री: हां जी, लोगो को सावधान करने के लि ये कि वे टीके लगवाएं सरकार ने हिन्दी और अंग्रजी दोनो में पोस्टर छपवा

कर बांटे और उस के अलावा आकाशवाणी जालन्धर तथा देहली से रेडियो पर प्रचार किया। इस के अलावा नवम्बर 1966 से बड़े पैमाने पर टीके लगाने का प्रोग्राम चालू किया और एक लाख 98 हजार से अधिक लोगों को टीके लग चुके है। इस नामुराद बीमारी को दूर कने के लिये और भी कई उपाय किए गए है।

Construction of Spurs in Uplana Minor

***174 Shri Ran Singh:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

a) The total Number of Spurs (Thokren) constructed on the Uplana Minor, District Karnal, together with the dates of their construction:

b) The purpose for which the Spurs mentioned in part (a) above were constructed;

c) The effect of these Spurs on the distribution and flow of water to irrigate the total area of villages benefited by Uplana Minor?

Shri Mani Ram Godara: (a) All were constructed in July 1966.

(b) As the full supply level had not been attained in the Minor, the profile walls were constructed to raise the water level to the designed level to enable the outlets the draw their authorized discharge.

(c) The water was equitably distributed in all the outlets and there was no further complaint of shortatge of supply in any outlet.

श्री रण सिंहः इस सवाल के पार्ट (बी) में वजीर साहिब ने फरमाया है कि चूंकि पानी की फुल सप्लाईं नहीं दी जा रही थी इस लिये प्रोफाइल वाल्ज बनाने की जरूरत पड़ी थी ताकि पानी पूरा जा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि उस से आगे चल कर अगर पानी की सप्लाई पूरी न हो तो वहां पर भी प्रोफाईल वाल्ज बनाई जाएंगी?

मंत्रीः प्रोफाइल वाल्ज ही इस का इलाज हीं, उस में ऐडीशनल पाईप भी फिट किए जा सकतें है।

Shri Ran Singh: In part (c) of the reply, it is stated:

" . there was not furt her comlaint of shortage of supply in any outlet."

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह उन्होने गलत जवाब भेजा है। मौजूदा सरकार को शिकायतें भेजी गई है। जिन के ऊपर मेरे दस्तखत भी है। इस लिये इस तरह का जवाब देना गैर–जिम्मेवारी की बात है।

मंत्रीः यह गौर–जिम्मेदारी के साथ लोगों को दस्तखत कर देते होंगे। मेरे पास तो कोई इन की दरखास्त नहीं पहूंची।

श्री रण सिंहः क्या वजीर साहिब बताएंगे कि अगर आगे के लिये उस माइनर के बारे मे इन को कोई शिकायत आए तो क्या पानी की कमी पूरी की जाएगी?

मंत्रीः यह हमारा फर्ज है। जो भी शिकायत आएगी उस पर पूरा गौर करने के बाद शिकायत दूर करने की कोशिश की जाएगी।

Extension of Uplana Minor.

***176. Shri Ran Singh:** Will the Minister for irrig ation and power be pleased to state-

a) Whether ther is any proposal under the consideration of Government regarding the extension of Uplana Minor in Karnal District, from R.D. Nos. 50750 to 56500;

b) Whether the local Panchayats or people have deposited any money in the Government Treasury in this connection; if so t he details thereof and the latest position in the matter?

Shri Mani Ram Godara: (a) Yes.

(b) Yes. Rs. 6600 were deposited by the land-owner s for the extension of Uplana Minor. The work has already been completed and the minor is now running from R.D. 0 TO 56500.

श्री रण सिंहः क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि जिला करनाम में उपलाना माइनर में पानी उतना हीं है जितना कि आउट लैट कि लिए आथोराइजड् है?

मंत्रीः इस में पानी परा चल रहा है।

Exemption form Better ment Levy

***232. Chaudhri Nasib Singh** (Put by Shri Bhagwan Dev Prabhakar on his behalf): Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the Haryana Development Committee headed by Pt. Shri Ram Sharma recommended in their report abolition of the Betterment levy from the farmers whose lands are irrigated by the Western Jamuna Canal; if so; the action taken by the Government thereon?

Shri Mani Ram Godara: Yes. The Recommendations are being examined.

Six units of the Right Bank Power House at Bhakra

***234. Chaudhri Rizaq Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be Pleased to state-

a) the number out of the six units of the Right Bank Power House at Bhakra Which have been commissioned into servie so far together with the date when each one of them was commissioned and also the time by which t he remaining units are scheduled to be commissioned.

b) Whether the high voltage 220 K.V. and othe rtransmitssion lines intended to transmit power to

Haryana form the above-said power-house had been completed before the commissioning of the 1st unit of the above-said Power-House; if not, the reasons therefore and the time by wih these are likely to be completed?

Shri Mani Ram Godara: (a) Out of the Five Units (not six as mentioned in the Question) to be installed three have been commissioned on the following dates:-

i.	Unit No. 1	25-5-66
ii.	Unit No. 2	7-12-66
iii.	Unit No. 3	16-3-67

The remaining two units No. 4 and 5 are scheduled to be commissioned in November, 1967 and March, 1968 respectively.

(b) No. Delay was mainly due to short supply of the material. The work is expected to be completed by September, 1968

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ट्रांसमिशन के लिए लाईन कम्पलीट होने की वजह स`अब बिजल कैसे सप्लाई की जा रही है?

मंत्रीः वाल्टेज की कमी है, लेकिन बिजली तो सप्लाई की जा रही है।

चौधरी रिजक रामः क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या वे लो–वोल्टेज की शिकायत की वजह से पूरी बिजली सप्लाई नहीं हो सकी?

मंत्रीः जितनी वाटर सप्लाई है उसमें तीन यूनिट चलतें है। उसी से बिजली सप्लाई हो रही हैं

चौधरी रिजक रामः क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या बरसात के मौसम में भी पानी की कमी है? बरसात में भी यह यूनिट्स नहीं चलते?

मंत्रीः बरसात में पानी की कमी नहीं होती।

Power Sub-Stateion at Village Fazalpur, Tehsil Sonepat.

***235. Chaudhri Rizaq Ram:** Will the Minister for irrigation and power be pleased to state-

a) Whether the power Sub-Station at village Fazalpur in Tehsil sonepat has been completed according to scheduled programme;

b) Whether the 182 K.V. transmission line from Panipat to the said station has since been completed:

c) If the answer to part (a) and part (b) above be in the negative, the reasons therefore and the time by which the transimission line is likely to be completed?

Shri Mani Ram Godara: (a)

(b) No.

(c) Due to delayed supply of essential material and some mistake in the erection studs of the Tower. Top priority has been given to the work and every effort is being made to complete it at the earliest.

चौधरी रिजक रामः क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सोनीपत में जो ट्रांसमिशन लाईन है वह कब तक कम्पलीट हो जानी चाहिए।

मंत्रीः वह सन् 1968 में कम्पलीट हो जाएगी।

चौधरी रिजक रामः क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि अकार्डिग टू शिड्यूल्ड प्रोग्राम यह खत्म कब होनी थी और इसमें कितनी डिले हुई है?

मंत्रीः इसमें कुछ गलती है जब गलती ठीक होगी तब काम चलेगा। देरी जो हूई है वह फांउडेशन ले करने में हूई है।

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फाउंडेशन ले करने मे जो देरी हूई है उस के बारे में सरकार ने कोई ऐक्शन लिया है?

मंत्रीः इसके लिए इन्कवायरी हो रही है। इन्कवायरी रिर्पोट आने के बाद ऐक्शन लिया जाएगा।

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस डिले होने के कारण कितना नुकसान हुआ है?

मंत्रीः इसके लिए सैप्रेट नोटिस दें। मेरे पास इसकी इन्फर्मेशन नहीं है।

Starred Question No. 236

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of starred Question No. 236. It is therefore postponed.

Question Hour is over now.

UNNSTARRED QUESTION AND ANSWER

Recovery of Stolen Property in the State

24. Shri Daya Krishan: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The estimated amount of property reported to have been stolen in the State during the period form Ist

November, 1966 to 1st May 1967 according to the information received in the records of various police stations;

(b) The amount of said property recovered during the said period?

Rao Birendra Singh:

(a) Property worth Rs. 9,22,277.51 Paise.

(b) Property worth Rs. 3,89,496.03 Paise.

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री अध्यक्ष: डा. मंगल सैन जी की प्रिविलेज मोशन थी, इसकी बाबत यह है कि श्री माडू राम ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और इस केस की तफतीरश हो रही है। इसके बाद केस अदालत में जाएगा। क्योंकि यह सबज्यूडिस केस है इसलिए मैं इसे मूव करने की मन्जूरी नहीं देता।

CALL ATTENTION NOTICE

श्री अध्यक्ष: एक काल अटैन्शन मोशन श्री दया कृष्ण जी का है। वह अगर चाहें तो इस पढ़ दें।

Shri Daya Krishan (Jind): Sir, I beg to draw the attention of the Government to an urgent matter of public importance created by the threatened hunger-strike by the Government Servants to be commenced from to-day the 13 the June, 1967 to get their following demands fulfilled:-

1) D.A. at the Central rate be sanctioned with effect from Ist May, 1967 as is given to the employees of the Punjab and Himachal Pradesh Governments;

2) That Half D.A. at the Central rate required to the deposited by the Haryana employees, be not deposited in C.T.D. account as an immediate relief is required in view of the high prices.

I therefore, urge upon the Government that immediate steps be taken for redressing the above-stated genuine grievances of the Government employees.

Mr. Speaker: I have admitted it. The hon. Minister may please make a statement in due course.

श्री राम प्रकाशः स्पीकर साहिब, मेरी एक काल अटैन्शन मोशन जो आठ तारीख को दी थी.....

श्री अध्यक्षः वह मैं ने डिसअलाउ कर दी है।

श्री राम प्रकाशः किस ग्रांउड पर की है?

श्री अध्यक्षः बात यह है कि इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकतीं बाकी ग्राउंड यह है कि वह अरजेंट पब्लिक इम्पार्टंस की बात नहीं है।

श्री राम प्रकाशः मै अर्ज करना चाहता हूं कि .....
...

Mr. speaker: It cannot be discussed when I have disallowed it. The hon. Member may, however, come to my chamber and I will satisfy him.

Mr. Speaker: I have to report the time-table fixed by the Business Advisory Committee in regard to the business to be transacted by the House. It is as follows:

The Committee met on the 9th June, 1967 at 10.15 a.m. in the Chamber of Speaker, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh. The following were present:-

1) Chaudhri Sri Chand, Speaker, ex officio Chairman.

2) Chaudhri hardwari Lal, Minister for Parliamentary Affaris.

3) Shri Mangal Sein

4) Shri Rizaq Ram.

Special Invitee

Shri Dev Raj Anand.

The Committee, after some discussion, recommended that the business in the House be transacted as follows on the days mentioned against each:-

Thursday, the 15 th June, 1967	Official Business be transacted instead of Non-Official Business, as below:-

	(i) Official Resolution. (Tiem-One hour). (ii) Leg islative Business.
Fridaya, the 16th June, 1967	General Discussion on Budget.
Saturday, the 17th June 1967	Off day.
Sunday, the 18th June 1967	Holiday.
Monday, the 19th June, 1967	Discussion on Demands for Grants.
Tuesda, the 20th June, 1967	Discussion on Demands for Grants
Wednesday, the 21st June, 1967	Discussion and voting on Demands for Grants.
Thurusday, the 22nd June, 1967	Appropriation Bill on the Budget Estimates.

Shri Mangal Sein (Rohtak): Sir, I beg to move-

That this House agrees with te recommendations contained in the Second Reort of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this house agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Biusiness Adviosry Committee.

Mr. Speaker: Question is-

That this house agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Biusiness Adviosry Committee.

Statement by the Minister for Irrigation and Power in regard to Call attention Notice No. 12*

Irrigation and Power Minister (Shri mani Ram Godara): The main demand of the Temporary Engineers of the Irrrigation Department relates to the revision of pay scales. Government have since decided to appoint a pay Revision Committee under the Chairmanship of the Finance Minister to go into the entire question of the revision of pay scales etc. of all the State Services. The demand of the Temporary Engineers would also be considered by the Committee.

2. Temporary Engineers actually working in the field in Haryana are attending to their duties normally. However, it has been reported that whereas the Punjab Temporary Engineers on deputation to the Bhakra and Beas Projects have gone on strike, the Haryana Temporary Engineees on deputation there have not gone on strike, but are “working to rule”. Since the Project is now under the administrative control of the Central Government, it is for them to take suitable action in the matter. They are being secially requested to ensure that there is neither any diminution nor disruption in the supply of wat er from Bhakra on account of the agitation of the Temporary Engineers working on the project.

3. The State Government Cannot consider the demands of the Temporary Engineers on deputation to the Projects in isolation and the whole question of the pay sales of Temporary Engineers in the State and on deputation to the Projects will be considered byour Pay Revision Committee.

Statement by the Minister of State for Rural Electrification in regard to call Attention Notice No. 15**

Minister of State for Rural Electrification (Major Amir Singh): It is unfortunate that the prices of essential commodities have been rising sharply, for some time past. The country is not self-Sufficent in foodgrains and huge quantities of wheat and other foodgrains have to be imported form other countries. There has been a serious drought in the countr y. U.P. and Bihar are already in the grip of famine. Such Conditions have a psychological effect all over the country. There is some tendency on the part of producers to withhold the stocks. Similarly, the consumers also tend to buy and store up more in such a situation.

2. The Government is very much alive to the problem of high prices of the necessities of life and is taking suitable measures to arrest the upward trend of prices as far as possible. Some of the measures which have been are being taken in this direction are given below:-

*Call Attention Notice No. 12 appears in the HVS Debates dated 6th June, 1967.

** Call Attention No. 15 in the HVS Debates dated the 7th June, 1967.

(Minister of State for Rural Electrification)

1) About 2700 fair price shops have been opened in the State for the distribution of wheat, atta, sugar and rice to the consumers at fixed prices.

2) Suitable reserve of wheat and rice is being built up for the rovincial Reserve for distribution to consumers through depots. This helps in keeping a check over the rising prices of foodgrains besides making available foodgrains to consumers at reasonable prices.

3) The maximum wholesale and retail prices of various varieties of rice have been statutorily fixed both for the producing and consuming area of the State. Under the Punjab Rice Price Control Order, 1964 (as amended in 1966). Accordingly, no variety of rice can be sold in the market at prices exceeding those fixed under the above-mentioned order.

4) All wholesale dealers in foodgrains, sugar and Khandsari have been licensed. The licensees are required to submit fortnightly stock

returns. This has been done to keep a check on the activitie of wholesale trade.

5) The enlarged zone of wheat and gram, which included the giant State of U.P. was responsible for very high prices of foodgrains. The State Governmnet tried its best to form a zone comprising of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Though it was not accepted by the Government of India, yet the formation of a single State Zone for wheat for Haryana is much better than the enlarged zone including U.P.

6) Regarding the prices and supplies of cement, kerosene, soft coke, bricks and vegetable ghee ation is being taken on the following lines:-

i. **Cement.**- Though Cement is a decontrolled item, yet prices thereof are fixed by the Industry in consultation with the Government of India and Cement stockists are required to sell cement at those fixed prices. In case of any malpractices that may be indulged in by the stockists, action can be taken by theDistrict Officers under the rovisions of the Punjab Cement prices and Display Order, 1966.

ii. **Kerosene.** - Wholesale and retail dealers licences have been issued by the District Magistrates under the provisions of the Punjab Kerosene Dealers Licensing Order, 1966 and the prices

are also controlled by the District magistrates under the provisions of Kerosene Fixation of Ceiling Prices Order 1966. The object of this order is oviously to enable to introduce healthy regulatory measures in the distribution channel to tbe best advantage of the consumers.

iii. **Soft coke-** Prices are fixed in the district by the District Magistrates according to a certain formula Prescribed by the Governmnet.

iv. **Bricks.**- Ceiling rices of bricks are fixed by the District Magistrates under the provisions of the Punjab Control of Bricks Supplies Order, 1956 and the East Punjab Control of Bricks Supplies Order 1949.

v. **Vegetable Ghee-** Prices of vegetable ghee are fixed by the Government of India. With a view to ensure that there may be no over-charging and to ensure Hydrogenated Oils Dealers Licensing Order, 1967 has been promulgated.

vi. The Punjab Commodities Price Marking and Display order, 1962 is in force in the State where under foodgrains and other essential commodities at prominent places in their business premises.

vii. Anti-smuggling measures in the State have been tightened to check unauthorized movement of foodgrains.

viii. Arrangements have been made in collaboration with the Statistical organisation of the Planning Department to collect weekly information about prices of foodgrains in various districts of the State and to ensure that the correct prices are reported by the Districts.

3. Eight Central Co-operative Consumers Stores are operating in the cities of Ambala, Yamunanagar, Karnal, anipat, hissar, Bhiwani, Rohtak and Faridabad. Besides these Stores, a Central University Co-operative Consumers store has been orgainsed at Kurukshetra only recently. In addition, 8 primary Consumers Co-operative Stores have been organized at Jind, Kaithal, Gurgaon, Palwal, Sonepat, Rewari and Sirsa.

4. The 8 Central Cooperative Consumers Stores which are functioning for the last 3 years have a membership of over 32415 The Stores are playing an important role by reating healthy competition with the private treade. Their sales turnover during the months of January, February and March 1967 was as under:-

January, 1967	24.81 lacs
February, 1967	28.87 Lacs
March, 1967	28.85 Lacs

These Stores have not been organized with any motive of profit but the object is to do service to the community and to hold the price line.

1. The Government has also advanced to Government employees an interest-free loan the purchase of wheat during t;he year 1967-68. Under this decision, a government servant is allowed an interest-free loan equivalent to two months' pay including dearness pay (subject to a maximum of Rs. 300) to the employees of Haryana Government drawing upto Rs. 500 Per month, who may wish to buy wheat for their own consumption during the year 1967-68.

The Governemnt are seized of the situation and would continue to do theirbest to hold the price line.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Chief Minister (Rao Birnedra Singh): Sir, I beg to lay on the Table-

1. The Appropriation Accounts of the erstwhile Government of the Punjab for the year 1965-66 and Audit Report, 1967.

2. The Finance Accounts of erstwhile Government of the Punjab for the year 1965-66.

3. The First Annual Report and Accounts of the Land Development and Seed Corporation Limited, Chandigarh, as required under setion 619 (3) of the Companies Act, 1956.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR THE YEAR 1967-68

Mr. Speaker: Before the House take up the next item on the Agenda, I want to make an observation. According to the programme adopted by the House today in pursuance of the report of the Business Advisory Committee, three days i.e. 13th, 14th and 16th June, 1967 have been allotted for the general discussion on the budget for the year 1967-68. During these days the members are at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein. But such discussion/speech should be strictly relevant to the matter before the Assembly.

According to rule 213 (3) the Speaker may if he thinks fit, prescribe a time-limit for speeches.

Accordingly, the leaders of the various groups will be givehalf-an hour end the hon. Members will get form 10 to 15 minutes each depending on their maintaining relevancy. On 16th June, 1967 at the end of the discussion the Finance Minister shall have the general right of reply.

दूसरे जो मैम्बर साहिबान अब तक नहीं बोले है, मैं पहले उन्हे टाईम देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आप मेरे से सहमत होंगें।

श्री दया कृष्णः जनबा सपीकर साहिब, मै यह समझता हूं कि मौजूदा बजट उतना ही अन–पापुलर है जितना कि यह मिनिस्टरी। (शोर) मैं इस मिनिस्टरी की अंत पापुलर इस वजह से कहता हूं कि वोटर्ज ने कांग्रेस के हक में वरडिक्ट दिया था।

मुख्य मंत्रीः क्या बहादूरगढ़ के इलैक्शन को भूल गए?

श्री दया कृष्णः उसको, जब तक दूनिया रहेगी कोई नहीं भूल सकता। वहां तो लोगों के साथ इस तरह की ज्यादतियां हुई है जो कि भूल नहीं सकती।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे कुछ मेम्बर साथी जो काग्रेंस टिकट पर रिटर्न होकर आए थें उन्होने कांग्रेस के फ्लोर को क्रास किया और एक दल बनाया जिसकी कि यह सरकार है।

इसलिए यह हरगिज भी पापुलर मिनिस्टरी नहीं कही जा सकती। एक साथी ने दोबारा इलैक्शन लड़कर कुछ अपनी हिम्मत दिखलाई लेकिन उस इलैक्शन में जो कार–गुजारी हुई वह हाउस के सामने पहले ही ब्यान हो चुकी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने पहले फरमाया था कि वे हर माह एक एक करके हर मेम्बर से इलैक्शन लड़ायेंगे.....

मुख्य मंत्री: अब आपकी बारी हैं। पहले आप लड़ाएं दीन मुहम्मद से।

श्री दया कृष्ण: लेकिन अब यह जहिर होता है ि कवे अपनी पहली बात पर अमल करना नहीं चाहतें तो, स्पी कर साहिब, जिन आदमियों ने कांग्रेस के फ्लोर को क्रास करके मिनिस्टरी ज्वाइन की है वे जब तक दोबारा इलैक्शन नहीं लडतें यह मिनिस्टरी अनपापुलर कहलाएगी। फिर हम तो इसे अनपापुलर इस लिए भी कहेंगे कि इसने टैक्स बहूत लगाएं है। गरीब आदमी पर टैक्स लगाए है। आज हर आदमी नाराज है क्योंकि सरकार ने कोई बड़ा रिलिफ उसको नहीं दिया है। मुझे इस बजट की दो चीजों से खुशी है नम्बर एक तो यह कि 70 लाख रूप्या जो हरिजनों के लिए इस बजट में दिया गया है वह अच्छी बात है और मैं इसको एप्रिशिएट करता हूं।

सिंचाई मंत्रीः आप सच्ची बात कहिए।

श्री दया कृष्णः मै तो सच्ची बात ही अर्ज कर रहा हूं।

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री दया कृष्णः दूसरी अच्दी बात की गई है गवर्नमैंट–ओण्ड टयूबवैल लगाने की। इससे काश्तकार का बहूत भला होगा। इन बातों के अलावा मै, स्पीकर साहिब, समझता हूं िकइस बजट में कोई ड्रास्टिक स्टेप्स हीं लिया गया। यह सारे का सारा बजट वैसा ही है जैसा कि पहला बजट था। हरियाणा नया बना है। हमारे हालात खराब हो गए है। जब तक इस बजट में कोई मजबूत कदन हो तब तक हमारी तरक्की होनी मुश्किल है। जैसा कि कहा गया है " Diseases desperate grown by desperate appliances are relieved or not at all." ठसी तरह से जब तक हमारे बजट में बडें कदम न हो तब तक हमारे दस प्रदेश की तरक्की होनी मुमकिन मालूम नहीं देती और मै ंतो यह समझता हूं कि और सब बातों को छोड़ कर हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अनाज की उज बढ़ानी चाहिए। लेकिन इसके लिए जितने कदम उठाने चाहिए। एक तो अनाज की उपज बढ़ानी चाहिए।

लेकिन इसके लिए जितने कदम उठाने चाहिए थे वे कदम इस में नहीं उठाए गए। दूसरे हमारी पापुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है उसको कम करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन वे भी इस में नहीं उठाए गए। मैनें एक बिल भी इस हाउस में पेश किया था। लेकिन वे भी इस में नहीं उठाए गए। मैनें एक बिल भी इस हाउस में पेश किया था। लेकिन हमारे लीडर साहिबने उसे बगैर पढ़े बगैर समझे रिजैक्ट करा दिया। अगर वह एडमिट भी हो जाता तो उस पर विचार होता, एक प्रापेगंडा हो जाता और मेम्बरों को उसके मुताल्लिक अपने विचार जाहिर करने का मौका मिलता।

श्री अध्यक्षः मै अर्ज करना चाहिता हूं कि जो फैसला मैने कर दिया उसको टच न किया जाए। वह तो मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन होगा।

श्री दया कृष्णः बहूत अच्छा जी। तो मै समझता हूं कि इन दो बातों के अलावा इस बजट में कोई अच्छी बात नहीं। अब मै टैक्सिज के मुताल्लिक अर्ज करूंगा कि इस वक्त क्या हालात है। आज हालत यह है कि गरीबों के ऊपर तो टैक्स लगता है लेकिन अमीर मौजे उड़ाते फिरते है। आज हालात यह है जो बड़े बड़े कारखानेदार है जो व्यापारी है जो बड़े

बड़े जमींदार है जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वे बड़े आराम से रहते है। हमारी सरकार को तो यह करना चाहिए थ कि वह अमीरो पर टैक्स लगाती और टैक्स से आने वाली रकम को गरीबों पर खर्च करती। मगर यहां तो उलटा हुआ है। यहां तो अमीरो पर कोई टैक्स नहीं लगा परन्तु गरीबों पर टैक्स लगे है।

हमारी जो गवर्नमैंट मशीनरी है इसके बारे में भी मै अर्ज करूंगा। वह अनसूटेबल मिनिस्टरी है। गवर्नमैंट की मशीनरी को संभाला जाए और मिनिस्टरी को स्टेबल किया जाए, क्योंकि जब तक स्टेबल गवर्नमैंट नहीं बनाई जाती तब तक कोई काम नहीं चल सकता।

(Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

मुख्य मंत्रीः आ जाइए फिर इधर ही।

श्री दया कृष्णः यह तो मै मानता हूं कि गवर्नमैट को स्टेबल किया जाए। मै यह बतलाना चाहता हूं कि आल–इंडिया लैवल की दो पार्टिया है एक तो काग्रेस और दूसरी जनसंघ। तो जब तक इन दोनो पार्टियों में से कोई एक गवर्नमैट में नहीं आती और एक पार्टी के रूप में नहीं आती इस तरह से

जोड़–तोड़ कर बनने वाली गवर्नमैंट हरियाणे में नहीं चल सकती। और न ही आफिसर्ज भी गवर्नमैंट के प्रभाव में रह कर काम कर सकते है। आज कल क्या होता है कि कई मिनिस्टर है और कई कई तरह के है जिनके अपने विचार किसी एक पार्टी से मेल नहीं खाते। कभी एक मिनिस्टर कोई आर्डर देता है और कभी कोई मिनिस्टर उस आर्डर के खिलाफ कोई आर्डर देता हैं। इस तरह से अफसरों को आर्डर कैरी आउट करने में दिक्कत होती है। (विघ्न) और गवर्नमैंट सर्वेंट्स की नागुफताबेह हालत है। साथ ही एक और बात जिसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि लोगों के दिल में यह बात घर कर गयी है कि बिना सिफारिश के कोई काम ही नहीं हो सकता। मै समझता हूं कि लोगों के दिलों से यह बात दूर करनी चाहिए।

जहां तक पब्लिक सर्वेंट्स के मुताल्लिक काम करने की बातें की जाती है मै समझता हूं कि यह उनकी हिम्मत है कि अंग्रेजो के बने हुए ढांचे को वह अब तक चला रहे है। वह खुद भी करप्शन नहीं करते और न करने देते हैं।

जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है मै यह कहना चाहता हूं कि पुलिस पहले भी थी और पुलिस

अब भी है लेकिन ला एंड आर्डर पहले से अब काफी खराब है। और पुलिस की हालत बड़ी ही अजीब है। किसी पुलिस स्टेशन पर चलें जाए और यह उम्मीद ले कर जाएं कि शिकायत सुनी जाएगी या रिर्पोट दर्ज की जाएगी तो यह नही हो सकता। वह तो एफ. आई. आर. भी नहीं लिखते , क्योंकि वह क्राइम को कम दिखाने के लिए यह तरीका ठीक समझते है। मैं सजैशन देना चाहता हूं दिल्ली की तरह रजिस्ट्रेशन की खुली छूटी होनी चाहिए। फिर जो गरीब आदमी है उन्हे पुलिस बड़ा टार्चर करती हैं। पुलिस के अन्दर मैं समझता हूं कि इतनी इनएफिशेंसी आ गई है कि केसिज होते रहते है और वे अनट्रेस्ड चले जाते है। चाहे वह केसिज डकैती के हों चाहे चारी के हो या मर्डर के हो उनका ये पता ही नहीं चला पाते। इस लिए इस तरफ मजबूत हाथों से कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके और वह शान्ति से निर्भय हो कर रह सके।

एजुकेशन की हालत भी खराब हैं। देखा जाता है कि जो गवर्नमैंट कालेज या स्कूल है उनके लड़के बहूत क फर्स्ट क्लास आतें है और बहूत कम पास होते हैं। उसके बरअक्स प्राइवेट स्कूलों और

कालेजिज में तालीम अच्छी होती है। इस लिए इस तरफ ध्यान देना की जरूरत है।

हास्पिटल्ज की हालात भी अच्छी नहीं। डाक्टर नहीं मिलते इस लिए यह लाजिमी है कि और मैडिकल कालेजिज खोले जाने चाहिए। यह बताया गया है कि 100 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज नई खोली जाएंगी। मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक दवा से इताना फायदा नहीं होता जितना कि ऐलौपेथिक से । इस लिए आयुर्वेदिक डिस्पैंसरीज के बजाए एलोपैथिक डिस्पैंसरीज खोल कर पैसा खर्च किया जाए। तो इस पैसे का ज्यादा मूल्य होगा।

टी.बी. की बीमारी का कोई हास्पिटल नहीं है। जब कि सैंकड़ो मरीज टी. बी. से पीड़ित हो रहे हे। मैंटल हास्पिटल भी कहीं नजर नहीं आता। इसलिए इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद मैं इंडस्ट्री की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हुं। इस बजट में तमाम का तमाम बर्डन लैंड पर चला गया है।हमारी गवर्नमैंट को चाहिए कि उसका बहूत कुछ ख्याल इस तरफ भी होना चाहिएताकि लैंड पर से कुछ बोझ कम हो सके और इंडस्ट्री की तरफ लोग ध्यान दे सके।

जब तक ज्यादा इण्डस्ट्रीज नहीं खुलेंगी तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। डिप्टी स्पीकर साहिब, मशीनरी से काम लेने के साथ मैनपावर की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है जो ि कइस वक्त बेकारों में सर्फ करते है। उन को अर ठीक धंधों पर लगाया जाए तो उस से एक तो उन को रोजगार मिलेगा दूसरे देश का भी फायदा होगा। इस के बाद मैं प्रापर्टी टैक्स के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। प्रोपर्टी टैक्स जो पहले 10 प्रतिशत था अब बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। एक मकान जिस में आदमी खुद रहता है उस पर इतना टैक्स लगा देना वाजिब बात नहीं क्योंकि उन में बहूत से गरीब आदमी होतें है। बाकी जिन्होनें किराए पर मकान दिए होते है। उनके उपर तो इस के अलावा और भी टैक्स लगते हैं। तो में समझता हूं कि यह टैक्स में बहूत ज्यादती की गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बस मैं इतना कह कर आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री दल सिंह (जुलाना): डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो बजट पेश हुआ है इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मै ज्यादा टाईम न लेता हुआ सिर्फ

टैक्सिज की तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज देश के अन्दर अनाज का संकट है और उसे दूर करने का अगर कोई साधन है तो वह केवल किसान है। लेकिन हमें अफसोस है कि उसे सहूलतें देने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहां आज हालत यह है कि दिन भर मेहनत कर के उसे शाम को खाने की रोटी नसीब नहीं होतीं ऐसे हालात में जब देश में अन्न का संकट हो मै समझता हूं जमींदारों को जितनी सहूलतें दी जा सकें उतनी ही थोड़ी है। इस बजट के अन्दर बजाए सहूलतें दे के उनके उपर वाटर रेट बढ़ा कर 2 करोड़ 12 लाख रूपए की रकम उन से वसूल की जानी है। मै समझता हूं यह उन लोगों के साथ भारी बेइनसाफी है जो देश की भूख को दूर करतें है। आप ने पांच एकड़ का मालिया मुआफ किया वह पांच या छः रूपए होगा लेकिन अगर वह पांच एकड़ वाला किसान उस में गन्ना पैदा करता है तो उस को बीस रूपया एकड़ हिसाब से अधिक आबयाना देना पडता है इस का मतलब यह हुआ कि किसान का मालिया में छूट मिलने पर भी लगभग 95 रूपये अधिक देने पड़ते है यह चीज क्या आप के लिए बेशर्म नही है? आज तक कांग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तान को किसी भी स्टेट में इतना ज्यादा टैक नही लगाया था जितना

कि आप की संकट सरकार लगारही हैं क्या यही आप की किसानो के साथ हमदर्दी ? इस के अलावा पैडो पर एक प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। एक तरफ आप कहते है कि पैदावार बढ़ाओ दूसरी तरफ आप टैक्स लगाते जाते है।

वित्त मंत्रीः यह तो परचेज टैक्स है।

श्री दल सिंहः हां जी वह भी किसानों पर ही है आठ लाख रूपए की रकम उन से ली जाएगी। फिर मुसाफिर टैक्स बना कर आपने 80 लाख रूप्ए की रकम लेनी है। डिप्टी स्पीकर साहिब, अमीर लोग तो मोटरों पर बहूत कम सफर करते है। इस लिए यह बोझ भी गरीबो पर हो पड़ता है। फिर कुरूक्षेत्र का जिक्र बड़े जोर से किया गया कि वहां कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था लेकिन उस का भी 46 लाख का टैकस किसानों पर ही लगाया गया है हालांकि किसानो के बच्चे वहां बहुत कम पढ़ते होंगे और ज्यादातार शाहूकारों के बच्चे ही वहां पर तालीम हासिल करतें हें अगर यह टैक्स आम जनता पर लगाया जात तो और बात थीं लेकिन यह जो लैंड रैवेन्यू पर 10 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाया है यह ठीक बात नहीं की गई। किसानों पर 3 करोड़ 46 लाख रूपए का बोझ डाला गया हैं तो यह सब चीजें

सरकार के बजट की भदी तस्वीर पेश करते है। हरियाणा प्रांन्त की जनता अगर उनक` अन्दर कोई गैरत है तो ऐसी सरकार को आर्यदा बरदाशत करने के लिए तैयार नहीं होगी। अब मै एजुकेशन की तरफ आता हूं। चौथे पांच साला प्लान के अन्दर 250 प्राइमरी स्कूलों को मिडल करना था और 110 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाना था। लेकिन इन्होनें इसी साल 98 मिडल स्कूलज को अपग्रेड कर दिया और 112 प्राइमरी स्कूलों केा मिडल स्कूल बना दिया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, इन्होनें अंधा धूध अपग्रेडिंग इस लिए की है क्योंकि इन को डर था कि हमारी मिनिस्टरी कायम नहीं रह सकती वरना कोई वजह नहीं थी कि जो टारगैट पांच साल का था वह पहले ही साल करते। फिर स्कूल अपग्रेड करते वक्त इन्होने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। एक एक मील के फासले पर हाई स्कूल और दो दो फर्लांग पर मिडल स्कूल खोल दिए है। चाहिए यह था कि जहां पर जरूरत थी वहां पर खोलते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर साहिब इन्साफ का यह तकाजा है कि जींद में तीन हाई स्कूल बनने थे वह तीनों इस सरकार ने इस लिए कैंसल करवाए क्योंकि वहां का मेम्बर कांग्रेसी है। यह पालसी ठीक नहीं है। आप को तालीम के मामलें में इस तरह का

कलूक नहीं करना चाहिएं। अगर मोल माल पर हाई स्कूल हो तो वह बेफायदा है लेकिन अगर 10/10 मील पर न होतो वहां जरूर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो सरकार नाजायज और निकम्मी हरकत करे और डंडे से काम कराना चाहता हो वह नहीं कर सकती। आप यकीन रखिए अगर आप ने इनसाफ पर नहीं रहना ओ आप देर तक पावर में नहीं रह सकते।

अब मै सड़को की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पैप्सू के बाद जींद के अन्दर कोई भी सड़क नहीं बनी। एक सड़क वहां पर बननी शुरू हुई थी वह भी बन्द कर दी गई। मै गुजारिश करूंगा कि बगैर किसी किस्म की पुलिटीकल फैक्शन के जा अण्डर डिवैल्पड एरियाज है जहां पर सड़के नहीं है वहां पर सड़के बनाई जानी चाहिए चाहे, वह किसी भी मेम्बर के हलके में हो।

अब मैं इन्डस्ट्री के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। चण्डीगढ़ में हरियाणा इण्डस्ट्रियल ऐग्जीबीशन 27 मई को करने की तारीक्ष अनाउंस की गई। फिर उस के बाद पांच जून फिक्स की गई। लेकिन वहं अगर जा कर देखा जाए तो सिवाए पीपों के और कुछ दिखाई नहीं देतां तो मै निवेदन करता हूं कि

इण्डस्ट्रों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जिन इलाकों में इण्डस्ट्री नहीं है उन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो इण्डस्ट्री के लिए रूपया मखमूस किया गया है वह उन जगहों पर ज्यादा खर्च किया जाए जहां पर कि पहले इन्डस्ट्री कम है।

डिप्टी स्पीकर साहिब 1965 के बाद 1966 में जो गवर्नर साहिब का एड्रैस हुआ उस में कहा गया कि जींद के अन्दर एक कीमरी लगाायी जाएगी। बड़े अफसोस की बात है कि वह आज तक कागज तक हो रही उस पर कोई अमली कदम नहीं उठाए गए। गवर्नमैंट के बड़े–बड़े आफिसर भी वहां फिरते रहते है लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। मै गवर्नमैंट से गुजारिश करूंगा िकइस और ध्यान दे।

अब मै गवर्नमैंट एम्पलाईज के लिए डी.ए. के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अभी गवर्नमैंट ने यह एलान किया है कि डी.ए. का आधा भाग सी.टी.डी. अकाउंट मे जमा करवाना पड़ेगा। मै समझता हूं कि यह नाजायज बात है। आप देख रहे है कि इतनी मंहगाई में कैसे एम्लाईज पैसा जमा कर सकते है। अगर जमा करना ळाा तो देने की जरूरत ही क्या थी। उस गरी एम्पलाई जो जो एक सौ रूपया तनखाह लेता है वह कैसे सीत्रटी.डी. अकाउंट में पैसे जमा करवा सकता है।

जिस भूखे आदमी को रोटी न मिले और कपड़ा पहनने को न मिले उसे हम कैसे कह सकते है कि तुम पैसे जमा करवाओ। मेरी समझ के मुताबिक यह ठीक नहीं। जो गवर्नमैंट ने डी. ए. को फैसला कर दिया तो गवर्नमैंट कम से कम दो सौ रूप्ये तक लेने वाले कर्मचारियों को तो छूट दे। इससे ज्यादा तनखाह वालों का जमा कर सकते थे लेकिन मेरी गुजारिश है कि दो सौ रूपये वाले कर्मचारियों का आधा डी.ए. जमा न किया जाए।

इसके अलाता जो किसानों पर टैक्स लगाया है उस के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अगर गवर्नमैंट यह चाहती है कि हरियाणा प्रान्त जो कि हाल ही में वजूद में आया है खूब फले फूलें तो किसानों पर लगाये गये टैक्स को री–कंसिडर किया जाए। जो किसान देश को आगे ले जाने वाले है उन्ही पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो देश कैसे आगे तरक्की करेगा? टैक्स के और कई जरिए है जैसे कई जगहों पर फजूल स्टाफ रखा हुआ है। रीआर्गेनाइजेशन से पहले सारे हरियाणा के लिए केवल एक डी.आई. जी. साहब और इसी प्रकार बहूत सा आसामियां है जिन पर बजट का बहूत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। यही हाल इन्स्पर्कटजर्ग का है जहां पहले एक इन्सपैक्टर होता था

वहां आज कतार खड़ी है जो कि खजाने पर बोझ है। उन को हटा दिया जाए तो बहूत सा रूप्या देश का बच सकता हे। कहीं कहीं तो फूड इन्स्पैक्टर इस बात के लिए रखे हुए है कि जो अनाज मंडियों में आता है वे पूछते है कि अनाज बिक गया है। ऐसे इन्स्पैक्टरों का कोई क्रिएटिव काम नहीं है। अगर आप इनकों कांटा–छांटी करें तो काफी रूपया देश का बच सकता परन्तु किसानां पर टैकस लगाने से खेतों में स्कावट होगी जो कि देश की तरक्की के लिए बड़ी भारी रूकावट होगी ।

इसके अलावा मैं ट्रांस्पोर्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: No interruption please.

श्री दल सिंहः मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि अगर ट्रांस्पोर्ट को नैशनलाइज कर दिया जाए तो काफी रूपये की आमदनी हो सकती है लेकिन जो टैक्स लगाया गया है उस से तो गरीबों पर ही बोझ पड़ेगा। नैशनलाइजेशन करने से किसान इस जुल्म से बच जाएंगे। इकसे अलावा जो शो टैक्स आपने लगाया इसको बेशक आप और बढ़ा दे क्योंकि इससे गरीबों पर कोई बोझ नहीं पड़ता। जो रूपया इस तरह से

बचाया जाएगा उस को हरियाणा की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, टयूब–वैल्ज लगाए जाएं, गरीब किसानों को फ्री लोन दें अैर कर्जे बगैरा दें। जितनी किसान कों सहुलतें होंगी उतना ही मुल्क तरक्की करेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा रूपया हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए लगाया जाएगा तो हरियाणा पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता।

एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैं यह महसूस करता हूं और देख रहा हूं कि जब से यह गवर्नमैट बनी है, स्मगलिंग का दौरा जोरों पर है। आज जब कि हरियाणा में अन्न संकट है – यहां से जौ और चना बाहर भेजा जा रहा है। इस स्मगलिंग से एक तो आदमी पन्द्रह पन्द्रह हजार रूपया कमाता है। यह सारा काम जी.टी. रोड के रास्ते से होता है। मै गवर्नमैंट से दरक्षास्त करता हूं ि कइस को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए ताकि हरियाणा प्रान्त के निवासी पेट भर कर रोटी खा सकें। मुझे शक है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कहीं यहां भी बिहार जैसी स्थिती न हो जाए। अब टाईम खत्म हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, आपने जो टाईम दिया है उसके लिए बहूत बहूत शुक्रिया।

श्री भगवान देव प्रभाकर (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त के वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो 1967–68 का बजट सदनल के सम्मुख रखा गया है यह हरियाणा की जनता की भावना का एक प्रतीक बजट है। इस बजट में हरियाणा प्रान्त की भावनाओं जनता की अकांक्षाओं का सुन्दर चित्र झलकता और प्रतिफलित होता है। यह बड़ी खेदजनक बात है कि कांग्रेस बैंचिज की तरफ से यह कहा गया है कि यह अनपापुलर गवर्नमैंट का अनपापुलर बजट है लेकिन मै बड़े जोरदार शब्दों में इस बात का प्रतिवाद करना चाहता हूं कि यह पापुलर गवर्नमैंट का पापुलर बजट है–अनपापुलर बजट नहीं है। हरियाणा प्रांत की लोकप्रियता को हरियाणा प्रान्त की सरकार की पापुलेरिटी को यहां सदन के सदस्यों ने और हरियाणा की जनता ने सिद्व कर दिखया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, जो बहादुरगढ़ के अन्दर बाई–इलैक्शन हुआ, इस उप–चुनाव के अन्दर जो कांग्रेस की हार हुई हैं यह इस जनता की जागरूकता की निशानी है। काग्रेस वाले इस इलैक्शन को अपनी प्रतिष्ठा की सीट समझते थे। इस को जोतने के लिए इन्होनें जो हथकण्डे खेले उसकी सारी दूनियां जानती है। लेकिन जनता में जागृति होने के कारण इनके झमेले में न आकर कांग्रेस को करारी हार दी। यहां के लोगों ने बड़ी जबरदस्त हुल्लड़बाजी की। मुझे

अच्छी तरह याद है कि डा. शम्भू दयाल जी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह अपमानित किया और उनकी धोती वगैरा फाड़ डाली। कांग्रेस की हिस्ट्री के अन्दर यह दाग ऐसा दाग है जिसे साल समुन्दर के पानी से धोने से भी नहीं मिटाया जा सकता। जिस वक्त डा. साहिब का अपमान हुआ तो उस समय उधर से एक जीप गुजर रहीं थी लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हे फूटी आंख भी न देखा और पत्थर की बौछारें की। इस पर मुझे एक कहावत याद आ गई––

''कुत्ते भौकतें रहें, कारवां चलता गया।''

बहादूरगढ़ के इल्क्शन में कांग्रेसियों ने जनता की रूह को नोटों से जीतने की कोशिश की, जनता के ईमान को खरीदना चाहा, और हर सम्भव प्रयास किया, लेकिन हरियाणा के नौजवानों ने चौ. हरिद्वारी लाल जी को पन्द्रह हजार वोटों से कामयाब बनाया। इस बात के साथ साथ कहतें है। कि इस सरकार में सीलीडैरिटी नहीं है यह सरकार अनस्टेबल है। मै इन सज्जन स्वप्नों की दूनियां में और मूर्खें के संसार में रहतें है। मै अपने संयुक्त दल की तरफ से इन कांग्रेसी बैंचो को चैलैंज पेश करता हूं कि वह अगर चाहें तो इस सरकार की स्टेबिलिटी टैस्ट करके देख लें। पहले भी कई मौके आए जबकि वह हमारी स्टेबिलटी देख सकते थे लेकिन संयुक्त दल को सरकार का नाम सुनते ही इने दस्त निकल जाते है। (हंसी) मगर फिर भी कहतें है कि यह

सरकार अनस्टेबल है। मैं उन से कहना चाहता हूं कि यह सरकार चट्टान की तरह मजबूत है और यह कांग्रेसी लोग इससे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाऐंगे। वह तसल्ली रखें यह बराबर पांच साल तक सरकार चलेगी और काई शक्ति इसे हिला नहीं सकती। मैं इस बजट के बारे में कहना चाहता हूं िकइस बजट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सभी महत्वपूर्ण विषयों की और ध्यान दिया है। इस वक्त हरियाणा में बड़ा भारी खाद्य समस्या से गुजर रहा है। यह सरकार बड़ी वरीता के साथ उसको फेस करती चली जा रहीं है। पहले हमें 6560 टन चीनी का कोटा मिलता था लेकिन संयुक्त दल की सरकार को यह समझ कर कि यह गैर–कांग्रेसी सरकर है इसके साथ स्टैंप मदरली ट्रीटमैंट करें ताकि यह सरकार जनता की नजरों में गिरं चीनी का कोटा अब घटा कर तीन हजार टन केंद्रीय सरकार ने कर दिया हैं जिस की वजह से आज सारे हरियाण में चीनी की भारी कमी है। भारतीय जनंसघ शहरों से अधिक चुन कर आया है और देहात से भी आए है और हमें देहात और शहरों में चीनी की कमी बहुत खटक रही हें मैं केंद्रीय सरकार पर यह आराप लगाता हू िकवह इस सरकार के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है जिस को किसी सूरत में भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के कानों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि आप बेशक चीनी की और भी कमी कर दें जनता इस को बरदाश्त करेगी, संयुक्त दल के मेम्बर गांव गांव में जा कर जनता को इस कमीं के कारण समझाएगे कि यह केंद्रीय सरकार इस कमी के लिए

दोषी है और जनता इस कमी का सरकार के साथ मिलकर मुकाबला करेगी। मै स्पष्ट स्प से यह कह देना चाहता हूं कि जनता को आप चीनी बेशक न दें वह यह सब कुछ बरदाशत करे के लिए तैयार नहीं है। (चीयर्ज) इसके लिए यह जनता जागरूक है। इसके साथ साथ राशन की कटौती से भी जनता में बड़ा भरी रोष पाया जाता है और यह सरकार इस कटौती को हटाने के लिए केंद्रीय सरकार से पत्र–व्यवहार कर रही है। खाद्य संकट पर काबू पाने के लिए यह सरकार बहूत कुछ कर रही हें और खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए और कृषि के सारे जितने तत्व संबधित है बीज,खाद, सिंचाई इम्पलीमैंट्स वगैरा उन्हें किसानों को उपलब्ध करने के यह सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है जिस के लिए हमारे वित्त मंत्री माहेदय बधाई के पात्र है क्योंकि के पात्र है क्योंकि उन्होने काफी राशि इन कामों के लिए बजट में रखी हैं। छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए उन्होनें 7.47लाख रूपये विशेष रूप से रखें है। हरियाणा के बड़े भारी क्षेत्र में कोई तीन हजार वर्गमील में जिला महेंन्द्रगढ़, भिवानी तहसील, तहसील झज्जर और रिवाड़ी तहसील में आज सूखा के हालात मंडरा रहे है और वहां कहते कैसे हालात पेदा हो गए है। गांवों में लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हे। मै सरकार का धन्यवाद करता हूं कि तमाम सूखग्रस्त इलाकों को राहत देने के लिए बीस लाख रूपये की व्यव्स्था की गई है। इसके साथ साथ कहतजैसे हालात का सामाना करने के लिए इरीगेशन फेसिलिर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन्तजाम किया गया है और कर रहे है। मिसाल के तौर पर गुड़गांव लिफ्ट

स्की, झज्जर की स्कीम, रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम और वैस्टर्न जमुना कैनाल स्कीम वगैरा चार–पांच योजनाएं चालू की है और इनकी तरफ ध्यान दिया है ताकि सूखाग्रस्त इलाकों को मदद दी जाए। इसके साथ साथ मै कहना चाहता हूं कि हरियाणा में इस वक्त 6690 गांव है और उन में से कोई 3600 गांव ऐसे है जिन में या तो पीने का पानी खारा है या उपलब्ध नहीं होता है। आज हालत यह है कि तहसील दादरी में पीने के लिए पानी लोग अपने ऊंटों पर पांच पांच मील दूर से जार कर लाते है। यह बिचारे इस तरह करते है कि बरसात के दिनों कमें जोहड़, टैंक्स बना कर उन में पानी इकट्ठा कर लेते है और सारा साल इस्तेमाल करते है लेकिन आज हालत यह हो गई है कि उनमें भी जो पानी उन्होने जमा कर रखा था वह सूख गया है जिस वजह से 3600 गावों में आज लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते है । मेरी माताएं और बहने दो दो सौ की तादाद में इकट्ठी हो कर अपने हाथों से घड़े और टोकनियां ले कर कतारें बांधे एक एक मील दूर पानी लाने जाती है और वहां क्लेश होते है गड़बड़ होती है और मछली मारकीट के दृश्य उपस्थित होते है। इसी तरह गांवो में या तो पानी खारा है या जोहड़ो, टैंको में सूख या है और मीलों दूर से पानी लाते है। मुझे प्रसन्न्ता होती है यह देख कर कि पानी की समस्या हल करने के लिए सरकार ने 66 लाख रूपए का बजट में प्रोवीजन किया है लेकिन मै यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि राशि बहूत कम है। इन इलाकों को पानी पहूंचाने के लिए कम से कम चालीस करौड़ रूपए की आवश्यकता हैं। अकेले जिला

महेन्द्रगढ़ के लिए 6 करोड़ 48 लाख रूपया पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस काम के लिए चार करोड़ रूपया रखा है। यह भी बहूत थोड़ी रकम है इसे ज्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही मे। निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग धंधों के लिहाज से भी हम काफी पीछे है और हमारे प्रदेश की 77 फीसदी जनता कृषि पर चलती हैं। जमीन पर के इस बोझ को भी हलका करने के लिए सरकार ने इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट के लिए इस बजट में चालू वर्ष के लिए 197 लाख रूपए का प्रोवीजन किया है। हरियाणा में इस वक्त 4018 छोटे उद्योग–धंधे और 948 रजिस्टर्ड फैक्टरियां हैं। सरकार ने काफी सूझ बूझ का परिचय दिया है जो यह रकम रखी है लेकिन मै यह अवश्य कहूंगा कि यह राशि थोड़ा हैं। सरकार ने शिक्ष की और भी काफी ध्यान दिया हैं। इसी वर्ष चालू बजट के अन्दर 112 प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड किया है। 98 मिडल स्कूलों को हाई और हायर सैंकडरी स्कूलों में कनवर्ट किया है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की और दिलाना चाहूंगा कि हाई और हायर सैकंडरी स्कूलों के अलावा हरियाण में जो केवल 6 पालिटैकनिक इन्स्टीच्यूशन्ज है एक मैडिकल कालेज है एक इंजीनियरिंग कालेज है ये बिल्कुल अपर्याप्त हैं। तकनीकी शिक्ष के लिए कुछ रूप्यों की व्यवस्था की गई है लेकिन वह अपर्याप्त है। इस वक्त हरियाणा के अन्दर इंजीनियरिंग कालेज और खाला जाए मैडिकल इन्स्टच्यूट खोला जाएं। रोहतक में मैडिकल कालेज के अन्दर अभी तक औषधियों

के विस्तार का अभाव हैं। इसी तरह से ईवनिंग कालेज और नाईट कालेज खोलने की व्यवस्था की जाए।

70 लाख रूप्या इस बजट के अन्दर हरिजनो के विकास की दृष्टि से रखा गया है। इन सब बातों को देखते हुए, डिप्टी स्पीकर साहिब मै समझता हूं कि यह बजट सम्पूर्ण विषयों को स्पर्श कर रहा है और यह सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि इस बजट को बना कर इसने बड़ी भारी दूदर्शिता का परिचय दिया है। मै इस सरकार को इस लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि इसने केन्द्रीय स्तर पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ कर्मचारियों को दिए जान वाले पैसे से पैदा होने वाले दो करोड़ रूप्ये के डैफिसिट तथा दूसरे डैफिसिट को पूरा करने के लिए जो टैक्सिज लगे है उनके बारे में मै याह कहना चाहूंगा कि वाटर रेट जो बढ़ा है उस पर पुनचिार किया जाए। उत्तर प्रदेश से जाहं पानी के फव्वारे चलते है कल कल नदियां बहती है हरियाणा के सूखे मरूस्थल की तुलना न की जाए। पंजाब जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसमें अभी पुराने ही रेट्स है। इसलिए यहां रेट बढ़ाना उचित नहीं होगा। यह मेरी प्रार्थना है। फिर पिछड़े क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कुछ प्रापर्टी टैक्स बढ़े है। लैंड रैवेन्यु के अन्दर अब 50 प्रतिशत सरचार्ज किया है। इसके बारे में भी मै प्रार्थना करूंगा कि यह ठीक है कि हरियाणा सरकार अपने डैफिसिट को पूरा करने के लिए प्रयत्न करेगी और उन प्रयत्नों को सार्थक बनाने में हम उसकी पीठ के

पीछे छाती तान कर खड़े और पूरी स्पोर्ट देंगे लेकिन लैंड रैवेन्यु के भार से तो किसान पहले ही मर रहे है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि संयुक्त दल की सरकार जिसको जनसंघ को पूरा स्पोर्ट है लैंड रैवेन्यु में बढ़ोतरी न करे तो इससे किसान लोगो को इनसैंटिव मिलेगा और उत्साह मिलेगा। इनके अलावा और भी बहूत सी किस्म के किसान के ऊपर जो टैक्स है और निके कारण उसकी कमर दूदी जा रही है इनके बारे में भी सरकार पुनविचार कर लें

इन बातों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय मै यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर टीचर्ज को कोठारी कमीशन की रिर्पोट को लागू करने की कमी रहती है। हरियाणा के अदर हमारे जो टीचर्ज बन्धु है वह एक दलित वर्ग है, समाज का एक उपेक्षित वर्ग है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहूत ही चिन्ताजनक है जबकि दूसरी तरफ वे समाज के बिल्डर है समाज के निर्माता हैं इन बातों को ध्यान रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय मेरा वित्त मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है ि कवे कोठारी कमीशन की रिकमैंडेशन्ज को मान लें।

बजट के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, एक और कमी रह गई हैं। वह है मजदूरों के बारें में। मजदूरों के लिए कोई भी प्रोवीजन इस बजट में नहीं किया गया है। कौन नहीं जानता कि आज बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्ज मजदूरों के साथ अन्याय करते हे। भिवानी में दो टैक्सटायल मिलें है। 9—8—66 को

एक मिल में दुर्घटना हुई थीह। उस दुर्घटना में छत गिरने से 12 आदमी स्वर्ग के अन्दर चले गए और 50 जख्मी हो गए। कितने अफसोस की बात है की 50 लोग आज वहां ऐसे है जो जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। किसी का पैर टूटा हुआ है।, किसी की टांग टूटी है किसी का हाथ टूटा हुआ है और किसी का कुछ टूटा हुआ है तो किसी का कुछ टूटा हुआ है। शोक की बात है कि इस एपिसोड की जांच करने के लिए जो एनक्वायरी कमीशन बैठा हुआ था वह भगवत दयाल जी की मिनिसटरी में सिरे नहीं चढ़ा क्योंकि 20 हजार रूप्या वहां की टैक्सटायाल मिल ने पिछले सरकार को 20 हजार दिया और उस सरकार ने उस मामले को ठप्प कर दियं इसलिए में अपनी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यह उस सारे मामले की जांच कराए। यादि कमीशन बिठाना पड़े तो कमीशन बिठाए जिससे कि इन गरीब मजदूरों को अधिक से अधिक कम्पैन्सेशन मिल सके।

श्री उपाध्यक्षः प्रीााकर जी, आपका समय हो गया है।

(Mr. Seaker occupied the Chair.)

श्री भगवान देव प्रभाकरः अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ मै ज्यादा न कहता हुआ यही प्रार्थना करूंगा कि इन टैक्सों के ऊपर जिनसे देहाती लोगो को आघात पहूंचा है और जिनको रूरल जनता बरदाशत करने को तैयार नहीं, पुनविचार किया जाएं अन्य सब बातों का इन बातें के अलाता जोकि बजट के अन्दर है।(कांग्रेस की तरफ से आवाज यही तो है असली बातें, बाकी है ही

क्या) मै पुरजोर शब्दों के साथ समर्थन करता हूं और मुझे विशवास है कि यह बजट आने वाले वर्ष में हरियाणा की जनता को वरदान सिद्व होगा।

Shri Faqir Chand Aggarwal (Ambala City): Mr. Speaker, Sir, with your permission I would like to place before the House the conditions obtaining in my Constituency as they are intimatel connected goodself knows full well Ambala has been most hard-hit by the reorganisation of the State of Punjab. Before the reorganisation to Punjab. Nalagarh has gone to Himachal. Even a part of Kharar Tehsil has also gone to Punjab. Thus, Ambala has been reduced to the Ambala, Naraingarh and Jagadhri, and a part of Kharar. I want to tell you, Sir that during its 20 years of mis-rule, the Congress Government has not been able to do anything for the development of Ambala. This Budget however as presented by the honourable Finance Minister gives us a ray of hope that something concrete will be done for the betterment of the people of Ambala. Water problem in Ambala, I may submit has been a burning problem for the last twenty years or even more. The Congress Government has not done even a little bit to improve the water-supply there. I am however grateful to the Transport Minister, Shri Lachhman Singh and the Deputy Minister Shri Ram Parshad, who took a lot of interest in this direction . On 3rd June 1967 they asked the Chief Engineer, Public Health to operate the tube-wells for a maximum time and it was for this timely help rendered by them that better conditions were restored there. Here it is a matter of Finance Minister regarding drinking warte-supply it has been stated. " A provision of Rs. 4 crores has been made in the State Fourth

Plan for water-cupply schemes and Rs. 66 lacs wil be spen for this purpose during the current year."

I will now request the honourable finance Minister to see that as many tube-wells as possible are sunk in Ambala by spending more money so that trouble of shortage of water is removed once for all.

So far as the development of education is concerned there is no medical or engineering ollege at Ambala. Ambala has been clamouring for it since long. It is however a matter of great pleasure to see that some substantial amount has been provided both for technical and other education in the State during the current year as well as for the Fourth Five-Year Plan as a whole.

Again, Sir so far as the sinking of tube-eells in Ambala is concerned, ther is no electricity available in most parts of the District. Thus there will be no point in sinking tube-wells if power is not available. I would request our worthy Finane Minister to provide as muh funds as ossible to solve this problem as Ambala has all along been ignored during the previous regimes in this regard.

Mr. Seaker, sir so far as the industrialization is concerned, I would submit that no attention was ever aid to establish industries in Ambala Either before or after the partition of the State. Even when Pandit Bhagwat Dayal was the Chief Minister no efforts were made to industrialize this area. The previous Governments did not try to look to the interests of Ambala at all. About four years back the Congress Government created industrial estate there, but no industries

were ever established ther and thus the industrial estate created is altogether closed up. Of course I do not know the reasons therefore. Therefore what I want to stress upon the hon. Finance Minister and the Government as a whole is that as much funds as possible should be provided or the industrialization of this area as at present there are no industries there. The Budget gives us a ray of hope that industries would come up in m area because provision has been made for the industrial development of the State and I do hop e that Ambala will recive sympathetic consideration at the hands of the present Government in this matter.

So far as electricity is concerned I amy submit mr. Speaker that there are about hundered villages on the Ambala-Nangal road which have not been electrified so far. It is requested that electricity should be provided there as early as possible.

So far as the roblems of the people of the area of Ambala are concerned I think no heed was ever paid by any of theerstwhile Govermnments. The ministers never visited that area. Even the representive of this are in the Assembly never cared to look to the troubles and needs of his constituents. So what I want to submit is that adequate provision should be made in the Budget for ameliorating the lot of the population of Ambala which is more than 85000. There are no factories there. There are no tube-walls and no electricity there in my constituency. Therefore, Sir Ambala is the most backward area in the State and requires special attention of the Government. So while I congratulate tlhe hon. Finance Minister for the Budget resented to the House I request that Government

should pay special attention to remove the problems of the people there because Ambala is a most backward area in the State.

श्रीमती लेखवती जैन (नांगल): जनबा स्पीकर साहिब हरियाणा की आंखे इस बजट की और लगी हुई थी । हम सोच रहे थे कि अभी तक तो हरियाणा बराबर जिसता रहा है ज्वाचंट पंजाब में हरियाणा की भलाई के लिये बहुत थोडा हिस्सा होता था, लेकिन अब अपनी स्टेट बनने के बाद सोचा था कि हमारी हालत को डिवैलप करने के लिये अपनी सरकार कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करेगी लेकिन इस बजट को देख कर जनता मायूस हूई और उसे खुशी नहीं हुई। और मै कह सकती हूं जैसा कि मेरे से अपले बोलते हुए भाई दया कृष्ण जी ने कह था कि यह अनपापुलर गवर्नमैंअ का अनपापुलर बजट है।

जनाब स्पीकर साहिब इस बजट के अन्दर 9 टैकसिज लगाए है। मै समझती हूं कि पंजाब की हिस्ट्र मे कभी इस किस्म के टैक्स नहीं लगाए गए जैसे ि कइस गवर्नमैंट ने अपनी छोटी आयु में लगा दिए है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स एक साल के लिये लगााना कबूल किया गया है मगर मै कहती हूं कि टैक्स की ऐसी बीमारी है कि एक बार लग जाए फिर छूटना बहूत मुशिकल होता है।

पनी के बिना अनाज पैदा नहीं हो सकता लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। हरियाणा में अनाज का बहुत कुछ

अभाव चावलों से पूरा किया जाता है। क्योंकि यहां चावलों की पैदावार भी होती है। तो इस सरकार ने इस पर भी 1 1/2 परसैंट का टैक्स लगा दिया यह गवर्नमेंट बड़ दम भरती थी कि हम 5 एकड़ और इससे नीचे वाले जमीन रखने वाले के उपर मालिया हटा चुके है लेकिन जिस आदमी के उपर यह टैक्स हटा है उसे उससे डेढ़ गुना ज्यादा आबयाना टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात हूई है?

जन संघ पार्टी के मेम्बर जिनकी तादाद सिर्फ तेरह है इक्यासी मेम्बरों में से वह बड़े फख्र कर सकते थे। मै यह बात चैलेंज से कह सकती हूं कि कांग्रेस बीस साल से राज करती रही मगर इसके किसी मेंम्बर ने इतनी शेखियां नहीं मारी जितानी कि री प्रभाकर जी ने शेखियां मारी और अलंकार लगाए। कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है कि जिसकी खुरचन का भी मूलय होता है। मै नहीं चाहती कि मै इस तरह की बातों में पड़ूं मगर जब इस तरह की बातें की जाती है उस तरफ की बेंचिज से तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ कहा जाएं

इन्होने बहादूरगढ़ इलैक्शन के बारे में बड़ी बड़ी शेखियां मारी। मै कहना चाहती हूं कि बहादूरगढ़ का वह जिक्र न करते तो अच्दा तोता। उसके तबसरों से तो इनकी गर्दन शर्प से झुक जानी चाहिए थी। प्रभाकर जी तो बोलते ही रहते है और जनसंघी हुल्लडबाजी करते ही रहते हैं और झूठ बोलना उनका काम है —— (इंट्रप्शन)

श्री मंगल सैन : यह लफज अनपार्लियामैंटरी है यह तो इन्हे विदड्रा करना चाहिए।

श्रीमती लेखवती जैनः मै यह लफज स्पीकर साहिब के कहने से पहले ही विदड्रा कर लेती हूं क्योंकि मुझे पता है। मगर जिसकी जो आदत हो उसके बारे के कहना पड़ता है।

स्पीकर सहिब मै भी उस इलैक्शन में मौजूद थी। वहां जिस तरीके से वोटिंग हुई उस से मै समझती हूं कि डैमोक्रेसी का गला घोंटा गया है वहां वोटों के राज को बिल्कुल खत्म किया गया है। इनके मिनिस्टर्ज ने वहां पर जा जार कर जनता पर अपना हर तरीके से दबाव डाला और लोगों को कई तरह के लालच तथा चकमें दिए। इन्होने सारी ऐडमिनिसट्रेटिव मशीनरी का दुरूपयोग किया जोकि डैमोक्रेसी के असूल के खिलाफ था। इस के अलाता बाहिर से लोग ला ला कर देहातो में बोगस वोटें डलवाई गई। इस का सबूत यह है कि वहां 150 बोअर ऐसे देखे गए जिन की उंगलियों पर पहले ही निशान लगे हुए थे। मैने खुद मलौटी गांव के अन्दर देख वहां हरिजानों के दरवाजों पर 10/10 जमींदार खड़े कर रखे थे उन को तंग करने के लिये और वह उन को कह रहे थे कि आप ने सैंट्रल सरकार से इन्तजाम करवा लेना था िकवह आ कर तुम्हारी मदद करती। दौलता साहिब ने जो यह बात कही थी कि वहां पर सैंटर की पुलिस आई हुई थी यह बिल्कुल गलत बयानी है। पुलिस इन की अपनी ही थी। जब मै वहां पर गई तो इन की पुलिस ने मुझे बाहिर ही रोक दिया और अन्दर नहीं जाने

दिया और जालीं वोटें भुगताई गई। स्पीकर साहिब, अगर इसी तरह चुनाव होने लगे ते डैमोक्रेसी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। जो कुछ वहां पर आप ने किया असे लिए आप को शर्म महसूस करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः आप सारी बातें ऐसी कर रही है जो कि इलैक्शन पैटीशन में आनी चाहिएं। आप कोई और बात करें।

श्रीमती लेखवती जैनः स्पीकर साहिब, वित्त मंत्री साहिब ने अपनी बजट स्पीच में बताचा है कि शिक्ष को फैलाने के लिये सरकान ने 112 प्राइमरी स्कूल मिडल तक किए है और 96 मिडल स्कूल्ज को हाई स्कूलज बनाया है।

श्री अध्यक्षः देखिए जी, समय तो आप का हो गया है।

श्रीमती लेखवती जैनः जनबा जितना समय प्रभाकर जी ने लिया उतना समय में जरूर बोलूंगी।

एक माननीय सदस्यः यह तो एक ग्रुप के लीडर के तौर पर बोले है। वह जन संघ ग्रुप के है।

श्रीमती लेखवती जैनः अब कोई जनसंघ ग्रुप नहीं हैं वह तो संयुक्त दल में मिल गया है।

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंअ आफ आर्डर सर। स्पीकर साहिब मै आप का रूलिंग चाहूंगा कि कोई माननीय मेम्बर आप के बार बार रोकने के बाद भी कया यह तुलना कर सकता है कि क्योंकि फलां

मेम्बर इतना बोता है इसलिये मै भी उतना ही बोलना चाहती हूं। अगर उन की कोई मौसी भतीजे जैसे रिश्ते नाते वाली बात है तब तो और बात है।

श्रीमती लेखवती जैनः स्पीकर साहिब, मै भी कभी इसी कुर्सी पर बैठा करती थी जिस पर आप बैठें है दो मिनअ मुझे और बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्षः आप को तो कुर्सी का गम खाए जला रहा है।

श्रीमती लेखवती जैनः जनबा स्पीकर साहिब मै इस हाउस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि 112 प्राइमरी स्कूल्ज अपग्रेउ करेक मिडल बनाए है और इस के अलावा 96 मिडल से हाई किए है। जनबा स्पीकर साहिब यह बात अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जो स्कूल चार सालों में अपग्रेड होने थे उन में से आधे से अधिक तो इन्होनें अपनी गवर्नमैंट को पापुलर बानाने के लिये पहले ही साल में अपग्रेउ कर दिए है। लेकिन जो आठवीं तक किए है उनमें सिर्फ एक एक टीचर भेजा है और एक ही जमात चालू की है। इस से लोगों को क्या लाभ होगा। इसके अलावा जिन इलाको में स्कूलों की ज्यादा जरूरत थी उन इलाकों को नजरअन्दाज इस लिये किया है कि वहां से कांग्रेसी एम.एल.ए. चुन कर आए थे। मैं कहती हूं कि अगर आप इस तरह की बेइन्साफी करते रहेंगे तो आप पापुलर बने की बजाए जयादा अनपापुलर

होंगे। आज इनके शिक्षा मंत्री या राओ साहिब यहां पर होते तो मै उन को बताती कि मेरे हलके में एक खुडा गांव है। वहां 80 साल से प्राइमरी स्कूल चला आ रहा है। वहां के लोगो ने गवर्नमैंट से बगैर मदद के 5/6 पक्के कमरे बनवा रखे है बगीचा वगैरह लगाया हुआ है और 80 एकड़ जमीन उस के नाम कर रखी है। डी.ई.ओ. ने उस को मिडल तक अपग्रेउ करने के लिये नम्बर एक पर रिक्मैंड किया था लेकिन इन को शर्म आनी चाहिए इन्होने उस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया।

इसके अलावा स्पीकर साहिब यह इस बात के लिये फख्र करते है कि हम ने इतना रूपया ट्यूबवैल्ज के लिए रखा है। स्पीकर साहिब, अगर यह लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते ते समझ नहीं आती कि इतना रूपया खर्च करने का क्या फायदा है। अगर एक आदमी को प्यास लगी हो उसे पानी न दिया जाए और दूसरे ने शरबत पी रखी हो उस के लिए एक घड़ा ला कर रख दिया जाए तो उस का क्या फायदा है? जहां पर लागों के पीने का पानी नहीं वहां पर पहले इन्तजाम करना चाहिएं स्पीकर साहिब हमारी तहसील मे एक भी सरकारी ट्यूबवैल नहीं हैं करनाल जिला भी हरियाणे में ही है रोहतक का जिला भी हरियाणा में ही हैं। स्पीकर सहिब यह बड़े अफसोस की बात है कि मेरे जिला अम्बाला में बहूत कम टयूबवैल्ज है। हरियाण के दूसरे जिलों में फिर भी कुछ न कुछ है लेकिन अम्बाला जिला में कोई टयूबवैल नहीं है। इस इलाका के साथ बहूत बेइन्साफी है। यह जो

नई सरकार हमारे सामने आई है हम देखेंगे कि अम्बाला जिले को कितने टयूबवैल्ज देगी। अगर इसी तरह करती रही जिस तरह से यह पिछले महीनों में करती रही है तो मै समझती हूं कि यह कोई पापुलैरिटी हासिल नहीं कर सकती। पापुलर सरकार होने के लिये ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

हरियाणा प्रांत में जस समग्लिंग हो रही है उसको दूर किया जाना चाहिए। जी.टी. रोड पर बहूत ज्या स्मग्लिंग हो रही है। आप देहात में जा कर देखें चीनी का एक दाना भी नहीं मिलता जबकि ब्लैक में तीन रूप्ये किल्लों चीनी जितनी मर्जी ले लों अगर इस तरह से ब्लैक होती रही तो गरीब लोगो को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पडेगा।

स्पीकर साहिब हरियाण में अभी पिछले दिनों एक जिला में दूसरे जिला में अनाज ले जाना बंद कर दिया था जिससे हर जिला में अलग अलग भाव थे। लोगों को अनाज खरीदने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पहले करनाल के जिला से बहुत अनाज अम्बाला जिला में आता था। जब पब्लिक ने शोर मचाया तो इस सरकार की आखें खुली। अब एक जिला से दूसरे जिला में अनाज जा सकता है। आज जी.टी. रोड पर और राजस्थान बार्डर पर जो स्मग्लिग हो रही है उसकी छानबीन की जाए और जनता की दिक्कतों की तरफ ध्यान दें।

Chaudhri Debi Singh Twetia (Hathin): Mr. Speaker, Sir when teHaryana State emerged on the

political map of India ther was a general impression that this State of sturd and brave people is going to be number one State in prosperity and development in no time. But very soon that impression has slumped. The political leaders f Haryana have behaved in such a manner that they have brought discredit to themselves and to te State. The impression that this State is going to be most prosperous was not unjustified especially when we hear about Isreal the tiny State with an area of almost half of Haryana and with less than 1/3rd population of Haryana can be so prosperous and strong. But what is required is a dynamic leadership determined people with missionary zeal to achieve that goal and it is that spirit and that dynamism and that secular outlook that is lacking. On the contrary what we see today is that Haryana Government is sometimes associated with this caste or that caste; even in the Assembly people are seen talking nothing else but about castes. Whata sorry state of affairs is prevailing here? Poson of castism has been injected in the body politic of this State. We require a bold step to remove it and the only way to do it is that all political leaders should get together and they should decide upon a code of conduct that in future such thing s\would be avoided otherwise the future of this state would be very black.

The budget proposals which we are dicussing depict a very sorry state of affarirs and sure signs of bankruptcyof this State are evident. To fill in the gap the government could not think of any otheralternative but to taz the most poorer section of the society i.e. the

peasants and even after resorting to the most undesirable step of taxing the poor there is a vast gap of deficit in the Budget. The taxes are such which can be straightaway termed as most anti-peasant and anti-rural people. This Government has been clamouring form the house top that it represents the peasants' has been torn as under b this budget. This Government has mobilized about 414 lacs of rupees to plug in the deficit and out of that mobilized amount the incidence of burden to the extent of almost 80 per cent falls on the ppeasants directly and the burden is such that it cannot be distributed by the peasant to other sections of the society.

This Government at theoutset with a view to getting cheap popularity announced that farmers holding five acres of land shall be exempt form the payment of land revenue on their holdings and in all gave a relief to the tune of Rs. 14 lacs. The Finance Minister in his Budget speech observes that-

" At a very small cost to the State exchequer this measure has been resulted in substantial relief to a large section of down-trodden peasantry who have heaved a sigh of relief"

But Soon after when the question cropped up as to how to fill up the large gap of deficit this very down-trodden peasantry became rich over night and became so rich that they were considered fit enough to bear the exhibited his antipeasant mentality by observing in his speech that the prices of foodgrains are quite high and why this extra money

should not be utilized by the Government in lieu of facilities and amenities that the Government provides to the peasants. The Hon. Finance Minister was critical of the high prices the foodgrains but he never thought that the prices of other goods which the farmer other commodfities at reasonable rate how can anyone think of milking the peasant of the extra prosperty brought about by the high prices of foodgrains. This mentality of the Government runs counter to the professed aim that the nation is looking to wards their study peasants to raise the national economy from the guagmire of national shame of going around begging for food. This budget would throw cold water on the enthusiasm of the peasant. If requisite food production is to be secured ten the peasant mus be assured in advance a fairly high price for his product so that he feels secured and frequent fluctuations in prices should be avoided. The Government should subsidize the consumer to the tune of Rs. 10 to 20 per maund and then this vicious circle of rising prices competing with pay rise can be broken. So, I would convey to the Finance Minister through you Mr. Speaker that he should reconsider his proposals and should find out other ways and means to fill in the gap rather than burden the already highly taxed poor peasantry with more taxes.

Now, I come to the specific questions, Mr. Speaker.....

Finance Minister: I am coming to that, Sir. For Kurukshetra university, the Finance Minister has tried to raise money to the tune of about Rs. 46 lakhs and that too again from the poor peasants and other small property holding people. To raise that much money there was antoher method

available also. That is to the present Punjab University, the affiliated Middle High and Higher Secondary Schools form Haryana contribute examination fee to the extent of about 40/45 lakhs. If such schools of Haryana are affiliated to the Kurukshetra University that amount would automatically to to Kurukshetra University. Whatever little gap is left ther after could be filled up by other methods, say be applealing to the richer section of the society for example the industrialists who flow their money like water just to help purchase M.L.A.s from this or that side of the House. I ask why can't they pay mmoney for this institution which is so necessary because in Kurukshetra University we have only 14 subjects that are taught there whereas in Chandigarh University ther are as many as 43 subjects taught. So there is great need that the Kurukshetra University should be developed further and educational facilites improved. But the way proposed by the Finance Minister to achieve the objective is not the proper way because it is not the proper way because it is not the poorer section of the society alone which is the only beneficiary.

So far as the question of irrigation facilities is concerned the Finance Minister has been quite specific in his Budget Speech at page 27. he has stated therein that in view of the necessity of development expenditure in other fields it is only just and proper that the irrigation services should be required to pay for their own working expenses and interest charges. He further says that this is a charge on services rendered to particular persons and there is no reason why other people in the State who do not derive any direct benefit form this service be required to pay for it. But I do not understand as to how the Hon'ble finance Minister could

convince himself on the other hand that the benefit from the Kurukshetra University goes only to peasants who cannot afford to give education to their children even up to middle or high School standard what to speak of graduate or post-graduate studies. I suppose there is hardly any person from the peasantry who goes to that University and gets the scholarship.

Now, Sir, Coming to other factors, ther is no indication in the Budget Speech of the Finance Minister that any concrete measures would be taken to check or reduce the rising prices. Even the short-sighted measure of creating a single food zone, has not resulted in bringing down the prices. In fact this measure has gone a long way in increasing smuggling on the borders and the stocks of food irains in Haryana are gradually being depleted by smuggling of foodgrains.

In order to improve the economy of the State it is but essential to adopt two specific measures. The first is the introduction of state trading in foodgrains and the second is the complete nationalization of transport industry in the State. It is only throught state trading that the producer can be assured of remunerative price for his produce and the consumer can get his requirements at reasonable prices. The foodgrains can also be subsidized by Government to lessen the hardship of the consumers. But in the Budget Speech nothing has been said about it. So far as the nationalization of the Transport industry is concerned fifty per cent of it has been nationalized so far. This is not enough. There should be cent per cent nationalization of this industry because that will

bring more money to the State Exchequer. I do not know what is the hitch. Why should the Government not nationalize the whole industry when it is beneficial not only to the Government but also to the traveling public at large?

Mr. Speaker, I want to stress one point more about education. As a result of the creation of Haryana State from Ist November, 1966 the present Punjab University at Chandigarh became an inter-state body corporate. Its name should then have been changd. It should have been named either Chandigarh University, or Haryana and Punjab University so far as Haryana is concerned is far from satisfactory. The share of Haryana in its teaching staff is only five per cent. The position of share in Administrative staff is still worse. We have the Vice-Chancellor from Punjab. The Registrar is from Punjab. The Deputy Registrar and the Chief Accounts officer also belong to Punjab . Again 35 Superintendents hail from Punjab. Of the 75 Assistants, only four belong to Haryana. Similarly out of 700 clerks only a dozen hail from Haryana. The Universtity has made 350 new appointments after 1st November 1966 and hardly few persons from Haryana have been aarded to students coming form Haryana. This sorry state of affairs should be put an end to by recourse to section 72 of the Punjab Re-organisation Act by requesting the Central Government to issue directives to the University. The Syndicate the Senate and various Faculties and Boards of Studies should be dissolved and in their plaed ad-hoc bodies be set up giving 50 per cent representation to Haryana. In various Departments of the University such as Chemical Engineering Architecture B.Sc., Engineering etc. etc. the seats for the students form Haryana be reserved. These are

some of the measures which the Central Governmnet must take through directives as they alone are competent to do so. Therefore to this aspect of the matter the State Government must pay immediate attention.

With these words, Mr. Speaker, I submit that the present Budget is the mst unpopular Budget. I do not know howcver whether the Government should therefore take immediate measures so as to give relief to that section of the society which has been unjustly dealt with. Thank you Mr. Speaker.

श्री लाल सिंहः (नारायणगढ़) स्पीकर साहिब, मै आपसे और आपके हाउस से दरखास्त करना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार बहूत से ऐसे कार्य कर जाती है जिनसे जनता परेशान हो जाती है, परन्तु खासकर सरकार ऐसे काम न करे जिसे जनता का नुक्सान हो चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या नान–काग्रेंस की। जो सरकार जनता का सुझाव रखना चाहता हूं। उनको मानना या न मानना सरकार की मर्जी है। सबसे पहले स्पीकर साहिब पीने के पानी का हर गांव में इन्तजाम होना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो वह है तो हमारे देश की। मगर देखा जाता है कि वोट नेले के बाद जनता को भूल जाते है। इस तरह वह जनता के साथ न्याय नहीं करते। बहूत से ऐसे गांव है जिनमें पानी न मिलने के कारण रिश्ते नाते भी बंद हो गये है। आपके प्लानिंग कमिशनर साहिब ने मरे कहने पर दो बार एक्स ई एन को भेजा भी लेकिन उन्होने भी

कागजों का ही पेट भरा, बनाया कुछ नहीं। सरकार से इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वह इस तरफ जल्दी ध्यान दे।

जहां तक अनाज का मसला है कि अनाज कम है और अनाज नहीं होता इस लिये मै एक ही अर्ज करूंगा। यह जो आज फैमिली पलानिंग को लागू किया गया है और जिस पर करोड़ो रूपये खर्च होते है इससे कोइ खास लाा नहीं। लूप आदि लगाने से आज बहूत सी औरतें बीमार है ं मेरी अपनी औरत बीमार है। इसके लिये मै यह दरखास्त करूंगा कि सरकार चार या पांच बच्चों की हद मुकर्रर कर दे। जो इससे जयादा पैदा करे उस पर टैक्स लगाया जाए। और जौ पैसा फैमिली प्लानिंग पर खर्च किया जा रहा है यह सारा टयूबवैल लगाने पर खर्च करना चाहिएं इससे सरकार को दो फायदे होंगे। एक तो फजूखर्च नहीं होगा और दूसरे आमदनी हो जाएगी। सरकार को सबसे जयादा जरायत पर जोर देना चाहिए जिससे अनाज का संकअ दूर हो सके। ऐसी कोई जमीन न रहे जिस पर सिंचाई का पानी न मिलता हो। (विघ्न) देखिए मेरी बात को सुनते जाइए। मै सरकार का बहूत धन्यावाद करता हूं कि इसने गवर्नमैंअ मुलाजिमों की तनखाह बढ़ा दी। लेकिन यह जो आधी बाद में पांच साल के बाद देने की बात कही है यह ठीक नहीं। आजकल की महंगाई को देखते हुए वह एक साथी ही दे दिए जाएं तो अच्छा होगा।

अब मैं अर्ज करूंगाा कि जिस इलाके में जैसे मेरे नारायणगढ़ हलके में जो ओलों से फसलें खराब हो गई एक तो

उनके खाने के लिए डिपू होने चाहिए और मदद के लिये ग्रांट मिलनी चाहिए और उनको तीन या चार फसलो का मामाला माफ होना चाहिए।

इसके बाद थोड़ा सा स्पीकर साहिब धर्मस्थानों के बारे में कहना चाहता हूं धर्म बहूत जरूरी है। धर्म के बिना तो रावण का भी राज नहीं चला था। जहां धर्म नही वहां कुछ नहीं। शरीर भी धर्म करने के लिए होता है। हमारे यहां धार्मिक स्थानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। इसके लिये स्पीकर साहिब मेरी अर्ज है कि सारे सूबे के धर्मस्थानों के लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करे ताकि वह कमेटी धर्म स्थानों की रक्ष कर सके। और ये सन्त और बड़े बड़े महन्त धर्म के पैसे को धर्म पर नहीं लगाते तो कमेटी को चाहिए कि जो धर्म–स्थानों के बारे में गवर्नमैंट को खास तवज्जोह देनी चाहिए और हिम्मत और ईमानारी से इस कार्य को करना चाहिए। स्कूलों के सिलसिले में भी स्पीकर सहिब मै एक बात अर्ज करना चाहता हूं। पहले हरियाण और पंजाब जब इकट्ठे थे तो यह कानून बनाया था कि स्कूल के बच्चों को फ्री बसों में ले जाया जाएगा और कुछ देर इस पर अमल होता रहा। लेकिन आज बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता खासकर प्राईवेट बसों वाले और सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं देती। खाली बसें चलती हे। मै ने देखा है। इसके बाद बात है स्कूल खोलने की। स्पीकर साहिब जिन लोगो ने अपने जेवर को बेचकर जमीन को बेचकर स्कूल के लिये बिल्डिंग तैयार की उनको इस

सरकार ने छोड़ दिया लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां बिल्डिंग भी नहीं स्कूल खोल दिए है। (विघ्न) देखिए साहिब मै किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मै तो जनता को बात कर रहा हूं। फिर, जनाब बड़े जोरों से कहा जाता है कि स्कूलो में पीने को पानी का इन्तजाम हैं। परन्तु सही बात यह है कि कहीं भी स्कूल में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। परन्तु सही बात यह है कि कहीं भी स्कूल में पीने के पानी का इंन्तजाम नहीं होता। अगर सरकार ने कोई आदमी इस काम के लिये स्कूल में रखा होता है तो उसका हमें तो पता नहीं कि वह कहां रहता है। उसके बारे में तो हैंडमास्टर साहिब ही जान सकते है कि वे उसे कहां भेजे रखते है।

स्पीकर साहिब, मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि रेलवे वालों की तरह बस स्टैंड पर भी पीने के पानी का इन्तजाम होना चाहिए क्योंकि यात्रियों को पानी न मिलने से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।

श्री अध्यक्षः अब आप का टाईम हो गया है।

श्री लाल सिंहः स्पीकर साहिब मेरी बातें तो सुन लो। मानना न मानना सरकार की मर्जी है।

स्पीकर साहिब, जिन लोगों की आंखे खराब है उन्हे सरकार को आई–कैम्पस में भेज कर उनकी आंखें बनवा देनी चाहिएं ताकि उनका कुछ भला हो सके।

जंगलात में स्पीकर साहिब जो दफा चार और पांच लगा रखी है वह नहीं होना चाहिए। लोगो को जरूरत के मुताबिक लकडी लेने की इजाजत होनी चाहिएं

गऊओं के लिए चरांद भी छूटने चाहिए। आप कहते है कि दूध नहीं है। दूध कहां से आए जबकि गऊओं के लिए चरांद ही नही? गऊओं के लिए जो फाटक रखे गए है वे भी टूट जाने चाहिए। यदि सरकार ऐसा करेगी तो यह बड़े धर्म का काम होगा।

स्पीकर साहिब, मै आप से और चीफ मिनिसटर साहिब से प्रार्थना करता हूं कि आपका कोई भी मिनिस्टर किसी शरीफ आदमी की बेइजजती नही कर सकता। अगर ऐसा करने से न हटा ते मै उस से बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि मैने उससे दाल मांगने तो नहीं जाना और अगर वह नहीं हटेगा तो मै हत्तक इज्जत का दावा करूंगा और उसे अदालत में खड़ा होना होगा।

श्री अध्यक्षः चलो, अब सब कु हो गया ं अब बैठ जाइए।

श्री हीरा नन्द (लोहारू): अध्यक्ष महोदय आज हाउस में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर बहस हो रही ळें इस में कुछ बातें ऐसी है जिनका मैं समर्थन करता हूं लेकिन कुद ऐसी भी है जिनका मै समथ्रन नहीं करता और अगर करता हूं तो समर्थन करते हुए दिल कांपता है। (प्रशंसा आपोजीशन की तरफ से) जिस वक्त यह सरकार बनी तो हरियाणा की जनता ने इसका बड़ा स्वागत किया। उस वक्त सरकार ने यह एलान किया था कि

पांच स्टैंडर्ड एकड़ तक के जमींदारों से रैवेन्यू नहीं लिया जाएगा यानी माफ कर दिया जाएगा लेकिन जब वित्त मंत्री महोदय ने लैंउ रैवेन्यू रायल्अी और वाटर रेट्स के बारे में मांग पेश की तो इस से लोगों को बड़ा धक्का लगा, लोगो में बेचैनी हुई। इसलिए मै यह दरखास्त करूंगा कि अभी भी वित्त मंत्री इस पर गौर करें, क्योंकि यह मेरा विश्वास है कि जब तक किसान को राहत नहीं मिलेगी तब तक अनाज की समस्यां दूर नहीं होगी।

मै देखता हूं कि लोहारू में पांच मील बेट एरिया पड़ता हैं। वहां के लोगों को खाने के लिए भी नहीं हैं। मगर सरकार ने आज तक कोई इंतजाम नहीं किया। वहां पर किसी प्रकार की दुकान का कारोबार या अनाज का आना जाना कुछ भी नहीं हो सकता हैं। अगर उन्हें साधन मिल जाएं तो उन लोगो का दावा हैकि वे सब से ज्यादा अनाज पैदा करके दिख देंगे।

जहां अनाज की कमी है वहां साथ साथ पानी की भीकमी है जो कि जिन्दगी के लिए बहूत जरूरी चीज है। भिवानी तहसील में पीने का पानी 5.—5, 6—6 मील से उठा कर लाना पड़ता ह। इस और सरकार को विशेष ध्यान देकर कदम उठाने की जरूरत है।

इसके बाद मैं हास्पिटल के बारे में कहना चाहता हूं। जनाब स्पीकर साहिब, सन 1965 से ले कर अब तक वहां पर

हस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है। वहां डाक्टर जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

लोहारू में मिनिस्टरों को और अफसरों को आना जाना पड़ता है मगर वहां पर कोई रैस्ट हाउस नहीं है। उसकी तामीर होना लाजिमी है।

उस एरिया में बहूत कहत पड़ता रहता है सड़के भी नहीं है और मीठा पानी पीने को नहीं है। लेकिन जहां पर है वहां अगर सरकार कुओं के लिए बिजली के कनैक्शन दे तो अनाज पैदा हो सकता है। जो कनैक्शन दिए जाते है उनके लिए सिक्योरिटी चार्ज की जाती है मगर हकीकत यह है कि लोगों के पास 105 रूपए भी नहीं है वे जमा कर सकें। इसलिए मेरा सजैषन यह है कि उन्हें सबसिडी दी जाए तभी वह इलाका जिंदा रह सकता है।

लोहारू जैसे इलाकों में काटेज इंडस्ट्री या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो भी यह सरकार अच्छी तरह से इंतजाम कर सकती है वह किया जाना चाहिए।

(Shri Faqir Chand Aggarwal, a member of the panel of Chairmen, occupied the Chair)

मैं स्कूलों के बारे में यही कहना चाहता हूं कि जाहं स्कूल है वहां 3–3 साल अध्यापक नहीं है। केवल कागजों पर स्कीमें बनाने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ टीचर्ज छः महीने के

कांट्रेक्ट पर रखे जाते है। अगर उनकी आवश्यकता नही ंतो उनको हटा दिया जाना चाहिए बजाए इसके कि वह तनखाह के लिए बैठे रहें और आखिर में कह दिया जाए कि अब आपका टर्म समाप्त हो गया और फिर वे लटकतें रहें। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भी टीचर्ज का ध्यान किया जाए। मै अंत में चेयरमैन साहिब यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार इस सरकार के वजूद में आने पर जनता ने इसका स्वागत किया था और इन्होंने भलाई की बातें की थी उनको पूरा किया जाना चाहिए और टैक्स का कुल्हाड़ा जो गरीब किसानो पर चलाया है वह हटाना चाहिए।

चौधरी हरि सिंह (हांसी): चेयरमैन साहिब, मै आपके द्वार इस बजट पर कुछ विचार रखना चाहता हूं। जब हरियाणें मे संयुक्त दल की सरकार बनी तो हरियाणे के किसानों ने खुशी मनाई कि हमारे सिरों पर जो बीस सालों से काग्रेंस का डंडा सवार चला आ रह था उस से हमे निजात मिली है लेकिन तीन महीनों के बाद हमारे वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो इस के अन्दर दो करोउ़ बारह लाख रूपए का आबयाना टैक्स हरियाणे के गरीब किसानो पर ठोंस दिया। इस के साथ ही उनक ` डपर एक करोड़ रूप्ए के और टैक्स किसी न किसी शक्ल में ठोंस दिए गए। इस बजट को किसानें पर टैक्सों का बजट कहा जा सकता है। इसलिए मेरी राओ सरकार से प्रार्थना है कि इन टैक्सों को कम किया जाए। इस के बाद सपीकर साहिब जो सड़कोपर खर्च किया जा रहा है मै उस की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता

हूं। हांसी बरवाला लिंक रोड के पिछले साल दस हजार रूपया प्रावाइड किया गया और उस के लिए आप की गवर्नमैंट ने मंजूरी भी दी है। लेकिन उस के बाद कहा कि एस्टीमेट गलत बना है उस बीस हजार रूपए का किया गयां इसी तरीके से हांसी रोड़ के लिए एक लाख और कुछ हजार रूपए का एस्टीमेट बना लेकिन दो महीने बाद पता लगा है ि कवह ऐस्टीमेट भी गलत बन गया था दो लाख का बनना था। मै निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस रूपए को कागजों तक ही महदूद रखना है ते मेरे ख्या लमे वह सड़के बननी मुश्किल हैं उन सड़को पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाना चाहिए। मै और ज्यादा न कहता हुआ आप से अंत में निवेदन करूंगा कि जो आप ने आबयाना टैक्स किसानों पर लगाया है उसे हटा दिया जाए। आप का शुक्रिया।

चौधरी राजेन्द्र सिंह (कैलाना): चेयरमैन साहिब चार पांच रोज से इस हाउस मे हम माननीय मेम्बरान की स्पीचे सुनते आ रहे है। तकरीबन सब मेंबरान ने आम तौर पर बहादूरगढ़ के बाई–इलैक्शन या कांग्रेस के मुताल्लिक हो अपनी स्पीचें दी है। चौधरी हरद्वारी लाल जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उस के बाद सब ने अपना अपना जोर लगाया। यह तो होता ही है कि एक जीतता है एक हारता है। लेकिन अगर किसी को कोई शिकायत है तो उस के लिए इलैक्शन–पैटीषन का रास्ता खुला है सारी बाते बजाए यहां हाउस में कहने के वहां पर लाई जा सकती है। चौधरी हरद्वारी लाल जी ने भी चैलैंज किया था कि अगर किसी को रंज

है तो वह हाउस से बाहिर जो कुछ कहना है कहे ताकि मै उस के खिलाफ प्रेसीर्डिग्ज कर सकूं और या वह इलैक्षन पैटीशन कर लें इस लिए मै भी कहता हूं कि खहमुखाह याहं पर एक दूसरे पर कीचड़ फैकने को कोई फायदा नहीं जब कि इलैकषन पैटीश्न का रास्ता खुला है। जब हरियाण बना तो हमे उम्मीद थी कि हमारा पिंउ छूअ गया है उन स आदमियों से जो हमारी शर्म लिहाज नहीं करते थें यह कोई छिपी हुई बात नहीं है मै बिना झिझक के कह सकता हूं कि जो हमारे बडत्रे भाई थे उन्होने हमारी जरा भर भी शर्म नहीं की थी और कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी हमें पीछे रखने में। हमे पूरा पूरा विश्वास था कि अब उन से हमार पीछा छूट जाएगा। आप बहादूरगढ़ इलैक्शन में राए मांगते रहे यह कह कर कि हम आप के लिय यह करेंगे वह करेंगे लेकिन जब यहां पर बजट स्पीच सुनी तो कोई काम की बात नहीं निकली। गवर्नमैंट चाहे किसी पार्टी की हो अगर वह अच्छे काम करती है तो हमे उस की सपोर्ट करनी चाहिए और अगर वह अच्छे काम नहीं करती तो उस के खिलाफ कहना चाहिएं। महज पार्टी के आधार पर सपोर्ट करना चाह अपोज करना कुछ माने नहीं रखता।

(Mr. deputy Speaker occupied the Chair.)

टब मै आप की मारफत इण्डस्ट्री के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। राओ साहिब यहां बैठे है उन से मै पूछना चाहूंगा कि आप आई.टी.आई. में लड़को को ट्रेनिंग किस लिए देते है जब कि उस के ाद उन्हे कारखानेदारों ने या आप ने किसी

काम पर नहीं लगाना। दसवीं पास कर के ट्रेनिंग लेने की बजाए अगर वह खेती कर ले तो बेहतर हैं अगर आप उन को आई.टी. आई. में ट्रेनिंग देते है। तो इस चीज की भी गारंटी दो कि बाद मे काम भी देंगे या उन को रूप्या दिया जाए ताकि वह अपना काम चालू करके रोजी कमा सकें। तमाम लड़के जो ट्रेनिंग ले कर निकलते है उन में से 95 प्रतिशत बेकार फिरते है काई भी कारखाने वाला उन को लेने के लिए तैयार नहीं होता । बल्कि जो इंजीनियर्ज भी है जिन्हे ऐक्स्पीरियेस होता है उन्हे भी कारखानेदार नहीं लेते अपने किसी अनऐक्स्पीरियेस्उ आदमी को ही ले लेते हें इस लिए मै आप से निवेदन करूंगा कि आप कारखानेदारां को सख्त हिदायत करं कि वे बगैर ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज की मार्फत आने वालों के किसी और को न लगाएं। यह अच्छी बात है अगर आप लड़को को पढाए लेकिन उन्हे रोजगार देने का भी प्रबंध होना चाहिए। महंत जी को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देहात वालों के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी हैं । राओ साहिब ीाी इस बात को अच्छी तरह समझते है कि जमींदारो का बजट इस तरह से नहीं होना चाहिए। मै उम्मीद करता हूं कि सरकार इस कम्पलेंट को दूर करने की कोशिश करेगी।

एक बात फिनांस मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं। तहसीलों में कई जगह तीन तीन तहसीलदार बैठे हुए है जिन्हे कोई काम ही नहीं। इसके अलावा दो नायब तहसीलदार भी होते

है जो कि बिल्कुल खाली बैठे हुए है। मै दरखास्त करता हूं कि इन्हें किसी दूसरी जगह लगाने की कोशिश करें ताकि सूबे के पैसे का ठीक ठीक इस्तेमाल हो सके ओर बचत भी हो सके। इस तरह कई दफतरों में डिप्टी सैकटरी हो सन 1950 में पहले दो–तीन ही डिप्टी सैकैटरी हुआ करते थे लेकिन अब पता नहीं कितने हो डिप्टी सैकेटरी हो गए है। इस प्रकार जो डिप्टी सैकेटरी वगैरह की पोस्टे है उन को हटाकर रूपए की बचत की जाए या जहां कोई पोस्ट हो वहां उन को लगाया जाए।

अब मै फ्लड्ज की बात करना चाहता हूं। आप कहते है कि ज्यादा अनाज पैदा करो। लेकिन तिना जमींदार कलटीवेट करते है वह फ्लड्ज खत्म कर देते हें इतना पैदा नहीं होता जिताना कि फ्लडज बहा करले जाते है। हमारे इलाका में ड्रेन नं. 4 है। उस में मिट्टी को हटाने के लिए गवर्नमैंट कहती है कि पैसा ही नहीं है। बरसात में हर सातल उस में मिट्टी भर जाती है और फ्लडज के कारण हजारों एकड़ भूमि खराब हो जाती है। सरकार इसकी रोथाम की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। यह नं. 4 ड्रेन सोनीपत और गोहाना के इलाके की डुबोती है। गवर्नमैंट को चाहिए कि जिस इलाका में इतनी पैदावार होती है वहां बान्ध बनवा दें ताकि फसल बरबाद होने से बच सके। बड़े बड़े आफिसरां को इस के बारे में हिदायत देनी चाहिए। लेकिन आफिरस बान्ध बनान के बजाये पैसा ख लेते है।

इसके अलावा मै फिनांस मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि किसानां पर से आबयाना बिलकुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो किसान अनाज पैदा करता है टैक्स भी वहीं दे जान भी वही मारे यह निहायत बेइन्साफी की बात है यह टैक्स उन गरीब आदमियों पर लगया है जिन के पास थोड़ी जमीन हैं जमीन के बेसिज पर लगा दिया जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। रोजाना चीजो के भाव बढ़ते ही जाते है और दूसरे आपने उन पर टैक्स लगा दियां इस से तो बेचार किसान पिस जाएगा। मै गवर्नमैंट से दरखास्त करूंगा ि कइस टैक्स को उठा दे ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

श्री राम पाल सिंह (पुंडरी): डिप्टी स्पीकर साहिब यह जो करंट इयर का बजट डिस्कस हो रहा है इस पर मेरे साथ्यिां ने अपने अपने विचार पेश किये है और बहुत बातों की तरफ ध्यान दिलाया है ं लेकिन एक बात मै जरूर कहूंगाकि मेरे साथियों ने बजट तो क्या पढ़ा होगा बजट स्पीच तक भी नहीं पढ़ होगी।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः आप दूसरों पर ऐस्पर्शन न डालें। आपको क्या मालूम कि पढ़ा है या नहीं पढ़ है?

श्री राम पाल सिंहः यह आपके ख्याल हो गया कि यह दूसरों पर ऐस्पर्शन है? कई साथियों ने अपनी स्पीय के शुरू मे कहा कि मिनिस्टरी अन–पापुलर है और यह बजट भी अनपापुलर है। जिस किसी ने भी बजट को बजट स्पीच को पढ़ होगा वह यह

नहीं कह सकता कि बजट अन पापुलर है। इससे जाहिर होता है कि जिन मेम्बरां ने स्पीच की है उन में से कइयों ने बजट को पढ़ा ही नहीं हैं। अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिये और अगर कोई ऐसी बात है जिससे किसी तबके या क्लास को कोई हार्डशिप हो तो उन्हे उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। अगर बजट स्पीच की अच्दी तरह से प्ए जाए तो पता लगता है कि हरियाण प्रांत की सरकार ने हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए कई सरहानीय स्टैप्स उठाए है। पिछली सरकार की जो कमियां है उन को दूर करने के लिए बड़े अच्छे स्टैप्स है जि के डपयर हरियाणा अच्छी उन्नति कर सकता है।

सब से पहला स्टैप जो लिचा है वह हरिजन वैल्फेयर के लिए लिया है। आजादी मिलने के बाद यह नारा लगाया जाता था कि हरिजन वैल्फेयर के लिए अधिक से अधिक रूपया रखा जाना चाहिए। पहले तो यह नारों तक ही महदूद रहा कोई क्रिएटिव काम नहीं किए हरिजन वैल्फेयर के लिए इस बजट में जयादा से ज्यादा रूपया रख गया हैं इसके बारे मे अगर पहला स्टैप लिया ह ता हसी सरकार ने लिया है। मै इस के लिए एक इल्तजा करूंगा। जिस तरह से में खच्र करने के लिए जल्दी कदम उठाए जाने चाहिए। जो जो काम शुरू करने है वे जल्दी शुरू किये जाएं। जो पैसा खासतौर पर हरिजनों के लिए तजवीज किया गया है वह इसी के डपर खर्च किया जाए । इस के अलावा जो रूपया

एग्रीकल्यर प्रोग्राम के लिए रखा है उसके बारे में भी स्टैप्स लिए जांए ताकि एग्रीकल्चर क्लास को इन्सेंटिव मिले।

बजट में जो रूपया इंडस्ट्रियल डिवैल्पमेंट के लिए रख गया है उसे भी स्कीमों के मुताबिक जल्दी खर्च किया जाना चाहिए क्योंकि देश में टैक्निकल हैड्ज की बड़ी सख्त जरूरत है। देश में जो टैक्निकल हैड्ज की कमी है वह बाहर से मंगवा कर पूरी नहीं की जा सकती इसी मुल्क में टैक्निकल हैंड्ज तैयार किये जाने चाहिए। आई. टी. आई. स्कूल्ज के लिए इन्स्टीच्यूशन्ज के लिए बजट मे काफी प्रोवीजन रखा गया है ताकि ज्याद से ज्यादा टैक्निकल हैंड्ज अपपनी स्टेट में पैदा कर सके। इस से एक तरफ तो अनऐम्पलयमैंट का मसला हल लोता है और शिकार किए जा रहे है ंअनएम्लायमेंट खत्म की जा रही है जिसक लिए यह सरकार सराहना की पात्र हैं। पिछली दफा कुछ ऐसा इम्प्रैशन दिया जा रहा था कि शायद रोडज और विलेज रोड़ज का काफी ध्यान रखा है और उनके लिए बजट में प्रोवीजन किया है जो कि काबिले तारीफ बात हैं। फैमिन एरिया की बात आज से नहीं जबसे हरियाण सरकार बनी है तब से यह प्राब्लम हर सैशन में डिसकस होती है लेकिन इस सरकार ने उसके लिए बजट में काफी रकम उन लोगो की तरफ ध्यान दिया है जो भूख प्यास से मर रहे है। पिछले दिनों जब गवर्नर ऐड्रेस पर बहस हो रही थी तो चीफ किनिस्टर साहिब ने यहां तक कहा कि सैंट्रल गवर्नमैंट हमारे कोटा मे से अनाज की कटोती न करे हां अगर हमारे हिस्सा मे से बिहार

को देने के लिए कुछ लेना चाहे तो हम देने को तैयार है लेकिन हमारी हातल भी ठीक नहीं है जिसक मतलब है उन्हे लोगो की तकलफ का पूरा एहसास है। फैमिन एरियाज में पीने के पानी का ख्याल रख गया है और वहां वाटर सप्लाई के लिए स्पैशल प्रोवीजन किया गया है। काफी दिनों से इस बात का काफी चर्चा था कि सरकारी कमचारियों को सैंटर का डी.ए. मिलना चाहिए और टीचर्ज के बारे में कोठारी कमीशन की रिपोट्र पर अमल होना चाहिए। उसके लिए सरकार ने बड़ सराहनायोग कदम उठाया है। उसने एक कमेटी बिठा दी है औरउसे रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का टाईम दिया है। यह टाईम फिक्स कर देने से साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत साफ है कि उन की जायज मांगो को माना जाए और उन को जायज रिलीफ मिलना चाहिए। इस के साथ साथ कमचारियों को फिनांशल पोजीशन टाइट होते हुए भी सैंटर का डी. ए. देने का एलान कर दिया हैं। ऐसी बातों की सरकार की हर किसी को तारीफ करनी ही चाहिएं लेकिन इसके साथ टैक्सों की तरफ ध्यान जाता है तो बहुत दूख होता है खसकर जो आबयाना बढज्ञया गया है। उस बढ़ाने के लिए बडी़ खूसूसती के साथ और मासूमियत के साथ बजट स्पीच में सिर्फ दो लफ्ज ही कह गए है कि ज्यादा नहीं सिर्फ दो लफज ही कहे गऐ है कि जयादा नहीं सिर्फ यू.पी वाले रेट्स ही लगाएंगे लेकिन मेरे ख्याल में बहूत थोड़े मेम्बरान को पता होगा कि यू.पी. के रेट्स क्या है। मै अगर आप के सामने वह रेट्स रखूं तो आपको पता लगेगा कि जो बड़ी खूबसूसरती के साथ दो लफ्ज पढ़ दिए गए है

वह इतने खूबसूरत नहीं है। मै कम्पेर करे आपको बताता हूं कि हमारे और उनके रेट्स क्या है? वह इस तरह हैः

फसल का नाम	हरियाण	यू.पी.
	पैरीनल कनाल रेट्स	
शुगरकेन	16 रूपए	32रूपए
	छूसरी कैनाल के रेट्स	
शुगरकेन	13.50	32रूपए
गार्डन वैजीटेबल्ज	8.24 रूपए	
व्हीट	8 रूपए	12 रूपए
बारले	8 रूपए	12 रूपए
टरद ग्रेनज्	7 रूपए	मालूम नहीं कर सका
अदर रबी क्राप्स	5 रूपए	9 रूपए
अदर खरीफ क्राप्स	1.50 रूपए	7 रूपए

अब आप देखें कि यह कितने खूबसूरत लफ्ज है जो स्पीच में कह दिए गए हैं कि कोई बात नहीं यू.पी. वाले रेट्स ही

लगा रहे है लेकिन अगर यह रेट्स लागू हो गए तो आप देखेंगे कि न सिर्फ रेट्स दुगने हो जाएंगे बल्कि बाज हालात में रेट्स चार गुना हो जाएंगे। इन्होने इतनी बड़ी बात को दो लफ्जों में बड़ी खूबसूरती और मासूमियत के साथ टाल दिया है। इस तरफ ध्यान देने की भारी जरूरत है। सरकार ने छोटे किसानों को भी पांच पांच एकड़ तक मालिया माफ करके रिलीफ दिया है और बहुत ज्यादा तादात में किसानों को रिलीफ पहूंचा है लेकिन इस के साथ साथ पांच एकड़ में से एक एकड़ को भी पानी लगाता है तो वहां रेट दूगना कर दिया हैं तो आप ही देख लें कि यह कैसा रिलीफ है। यह कहेंगे कि जहां छूट दी गई है उसकी भी नुक्ताचीनी करते हे लेकिन जो सही बात है वह कहनी ही चाहिए। एक तरफ तो कहते है कि हम ने मरला टैक्स माफ कर दिया और हम भी कहते है कि बडी सराहनीय बात की गई है लेकिन दूसरी तरफ उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरों का गला दबोच लिया गया है और वाटर रेट्स बढ़ा दिए है। मै कहना चाहता हूं कि यू.पी के रेट्स अगर आपने हरियाणा पर लागू करते है तो कर तो लेकिन हाउस को यह भी एश्योर करो कि जो फैसिलिटीज वहां पर पानी की है और जिस तरह वहां पानी दिया जाता है उसी तरह आप भी देंगे ताकि हम ज्यादा फसलें उगा सकें और किसानों को पेइंग कैपैसिटी बढ़ सके। और इस बढ़ाने के लिए एक जोन तोड़ कर उहे अपनी क्राप्स यू.पी. रेट्स पर बेचने की इजाजत दी जाए। दूसरे मैं यह अर्ज करना चाहता हं कि यह टैक्स

जो किसानों के ऊपर बोझ कन ज्यूमर पर नहीं डाल सकते जिस तरह कि व्यापारी सेल्ज टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल देतो है।

मुख्य मंत्रीः वे रेट्स में ऐड कर सकतें है।

श्री राम पाल सिंहः वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेट्स बढ़ने से रोकने के लिए सिगल फूड जोन बना दिए जाते है और इस के साथ साथ सरकार भी रेट्स को बढ़ने से रोकने के लिए मारकिट में चली जाती है जिस वजह से ओपन कम्पीटीशन नहीं रहता और रेट्स नहीं बढ़ सकते ं इसके साथ साथ आप ने यह भी देख है कि अगर कीमतें ज्यादा बढ़ती है तो कैसे हाहाकार मचती है जिस से कई प्राब्लम्ज पैदा होती है सरकारी कर्मचारी ज्यादा भत्ता मांगते है वगैरा, वगैरा। प्राईसिज राईज होती जा रहीं है। हर एम्प्लाई गवर्नमैंट को कहता है कि उसकी परचेंजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। खर्च इतना बढ़ गया है कि इतने पैसे में गुजारा नहीं कर सकते। इनकी इस मांग को सरकार स्तीकार करके इनके पैसे बढ़ा देती है जिसका असर यह होता है कि प्राईजि और हाई हो जाती है जिससे गरीब किसान भी अफैक्टिड होता है। परन्तु सरकार उसकी पेइंग कैपैसिटी को घ्यान में नहीं रखती और उसके डपर टैक्सिज दुगने बढ़ा दिए जाते है। उसके बारे में सोचना भी तो सरकार का ही काम है। (आवाज–यदि टैक्स न लगें तो सरकार को आमदनी कहां से हो) स्पीकर साहिब, कुछ आदमी कह रहे हैं कि यदि किसान पर टैक्स न लगे तो किस चीज पर टैक्स लगाया जाए।

श्री उपाध्यक्षः कवंर साहिब, टाईम हो रहा है।

श्री राम पाल सिंहः बहूत अच्छा जी। किसान के उपर और अधिक टैक्स लगाए बिना हमारे बजट में जा खसारा रह गया है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है इस के लिए स्पीकर साहिब मैं दो तीन बातों की प्रापोजल रखता हूं। सब से पहले तो अगर आप कहीं भी चले जाएं और घूम फिर कर किसी अप–टू–डेट आदमी से उसकी तारीफ पूंछे तो वह अपने आप को इन्स्पैक्टर बताएगां फिर वहां इस तरह का एक आदमी नहीं कई एक आदमी होंगे। कहने का मतलब यह कि इन्स्पैक्टरों की इतनी बढ़ौतरी होती जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मिसाल के तौर पर एक शाप इन्स्पैक्टर है और एक वेट्स एंड मैयर इन्स्पैक्टर है। दोनों का काम क्या है? उसके भी गांव में जाकर दूकानदार के तकडी़ बट्टे देखने होते है और उसने भी। तो क्या एक इन्स्पैक्टर काम नहीं कर सकता? क्यों न एक आदमी को हटा दिया जाए और एक आदमी उस काम को करें? क्या स्टेट की इससे इन्कम में बढ़ोतारी होगी या नहीं? यदि हां तो इस तरफ स्टेट को घ्यान देना चाहिएं

दूसरी चीज आप क सकते है आप हैती एडमिनिस्ट्रेशन में कमी। यह मरी बात नहीं बल्कि यहां एक कमीशन बैठा था जिस ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि " Top heavy administration at the Secretariat level and District level should be retrenched." इन बातों को कहने के लिए मुझे जो हाई रैकिंग या आई. ए. एस.

आफिसर्ज है और खासकर सैकेटरीज है माफ करेंगे। मुझसे यदि यह पूछा जाऐ कि सैकेटरीज कितने है ऐडिशनल सैकेट्ररीज कितने है और असस्टिेंट सैकेटरीज कितने है तो मुझे तो यह भी नहीं पता। इतने जयादा स्टाफ के कारण दो दिक्कतें हमें है। एक तो यह कि स्टेट पर फाइनैन्शनल बर्डन ज्यादा है। दूसरे काम में देरी बहूत होती है। एक कागज को इन सब के थ्रू गुजरने में लगभग एक साल कम से कम लगता है। तो इस के लिए मैं राओ साहिब से रिक्वैस्ट करूंगा ि कवे सैंट्रल गवर्नमैंट से कहें कि इतने ज्यादा आफिसर्ज हमारे बजट पर बहुत ज्यादा बर्डन है इसलिए हमारी जरूरत के अनुसार इतने हमें देदिए जाएं और बाकी वापिस बुला लिए जाएं ।तो इस तरह से भी फाइनैन्शनल इकानोमी हो सकती है।

तीसरी चीज जो मैं कहूगा वह यह है कि नसैसिटी पर तो आप टैक्स बढ़ाते जा रहे है परन्तु लग्जरीज की जो चीजें है उन पर आप टैक्स नहीं बढ़ाते। लग्जरीज को आम आदमी न खरीद कर बहुत अमीर व्यक्ति ही खरीदता है। इसलिए यदि इन चीजों पर आम जरूरत की चीजों की अपेक्षा टैक्स लगाएं जाएं तो सरकार की इन्कम इनक्रीज हो सकती है।

इन्कम को और जयादा बढ़ाने के लिए मैं एक और प्रोपोजल देना चाहूंगा। शायद आपको अच्छी लगे या न लगें और शायद जिनकी इन्कम ज्यादा है जो बहूत पैसे वाले लोग है धनाढ्य व्यक्ति है उन को यह बात बहुत ही बुरी लगे। परन्तु चाहे

कुछ भी हो मेरा यक एक क्ष्याल है और यदि इसे अमली जामा पहनाया जाए तो यह एक वरदान सिद्व होगा। बात यह है कि हमें इन्कम की कोई न कोई लिमिट फिक्स करनी चाहिए। लिमिट आप चाहे तीस हजार फिक्स करें, चाहे चालीस हजार करें या याहे पचास हजार करें। इस लिमिट से ज्यादा जिसकी इकम हो उसके अदर सरकार अपनी पच्चीस फीसदी शेयर रखे। इस तरह से स्टेट को करोड़ो रूप्ये की आदमदी हो सकती है क्योंकि इस वक्त स्टेट में करोड़ो रूप्या कमाने वाले लोग बैठे है....

मुख्य मंत्रीः वे सरकार को बहुत ज्यादा इन्कम टैक्स देते है।

श्री राम पाल सिंहः ठीक है कि वे इन्कम टैक्स देते है परन्तु इन्कम टैक्स देने के बाद भी करोड़ो रूपये की इन्कम उन को होती हैं तो , स्पीकर साहिब, मै अर्ज कर रहा थ कि यदि इस तरह सेहोजाए तो गरब लोगो को बहुत राहत मिल सकती है और उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है।

आखिर में, मै डिप्टी स्पीकर साहिब, कुरूक्षेत्रा युनिवर्सिटी के विकास के लिए जो लैंड रेवेन्यू पर एक साल के लिए टैम्परेरी सरचार्ज लगाया गया है उसके बारे में डिटेल्ज में न जाता हुआ थोड़ा सा अर्ज करूंगा क्योंकि हमारे यहां पहले ही लैंड रैवेन्यू ज्यादा है। यहां पर यह तो कह दिया जाता है कि हमारे यहां लैंड रैवेन्यू बाकी स्टेट्स के मुताबिक नहीं है परनतु यदि इसे

निकालकर देखें तो पला चल सकता है। फिर, यह ठीक है कि कुरूक्षेत्र युनिर्वसिटी का विकास होना चाहिए, परन्तु इस बात का भी तो जायजा लेना चाहिए कि जिन लोगों से यह टैकस लियजाता है उनके कितने बच्चे वहां एजुकेशन पा रहे हैं यदि उनके बच्चों को वहां शिक्षा पाने की फैसिलिटी नहीं मिलती तो उन पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है?

इन शब्दों के साथ, डिप्टी साहिब मै सरकार से आखिर मेंइल्तजा करूंगा कि बढती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए गल्ले की कमी को देखते हुए किसान के उपर यह जो उेडीशनल न बरदाश्त होने वाला बोझ लादा जा रहा है इसको मेहरबानी करके न लादे और इसको रीकन्सिडर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि कल ही इस बात का फैसला करे हाउस में चीफ मिनिस्टर साहिब या फाइनैन्स मिनिस्टर साहिब एलान करेंगे कि उन लोगों को कितनी राहत दी जानी है।

श्री राम प्रकाश (छछरौली, एस. सी.): डिप्टी स्पीकर साहि, राओ साहिब यहां है नहीं मै उन को मुबारिबबाद देना चाहता थ िकइस जट की स्पीच को पढ़ कर इतनी मायूसी हुई जिसको बयान करना कठीन है क्योंकि इस बजट में बैकवर्ड इलाकेां के लिए कोई तरक्की की बात नहीं रखी गई। डिप्टी स्पीकर सहिब गवर्नमैंट्स बनती है टूटती है लेकिन जनता वहीं की वहीं रहती है। मै तो इस बात के हम में हूं कि चाहे कोई सरकार आए उसका साथ देना सभी एम.एल.ए. साहिबान का फर्ज हो जाता

है। मै भी हमेशा सरकार के साथ को–आप्रेट करता आया हूं लेकिन जब किसी कंस्टीच्युएंसी या इलाके के साथ एक सौतेली मां का सलूक किया जाता है तो उस वक्त को–आप्रेशन की बात नहीं रहती लड़ाई हो जाती है डायरैक्ट। हमारा इलाका छछराली इतन बैकवर्ड है कि वहां के न जाने कितने लोगों ने आज तक रेल नहीं देखी है। वहां पर पानी पीने के लिए एक एक मील से पानी लाना पड़ता है। वह इलाका इतना जंगली है कि वहां के लोगों को जंगलियों में शुमार किया जा सकता है। मैं भी उन्ही का प्रेजेंटेटिव हूं और अगर दौलता साहिब होते तो मैं कहता कि वह मिनिस्टर भी बैकवर्ड होने के नाते जंगली है। लेकिन खेर मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है और कुछ नहीं कि वह इलाका बहु ही पिछड़ा हुआ हे। और तिस पर भी उस के साथ सौतेली मां का सलूक हो रहा है। मैने ज्वायंट पंजाब में भी उस वक्त की सरकार के सामे यह बात रखी थी कि हरियाणे में उसे शामिल करके हमारी डिवैल्पमैंट की तरफ ध्यान दो या पंजाब में शामिल करके इसकी तरफ ध्यान दो। सरदार लछमन सिंह ने कह थ कि अम्बाला जिले को पंजाब में कभी गिना गया और न हरियाणें में ही समझा गया और इस तरह उसकी डिवैल्पमैंट नहीं हो सकी। तों मै कह रहा था कि उस वक्त भी गवर्नमैंट ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था और सारा का सारा बजट या तो हरियाणे मे रोहतक को चला जाता था या फिर पंजाब को चला जातागि और इस तरह से हमारे इलाके को तरक्की नहीं हो सकी।

मैं, जनाब एक अपने इलाके में सड़क बन री हथी उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर एक मिनिस्टर जाते है, खुदा ने गंजे ाके नाखून दे दिए, एस मिनिस्टर ने वाहां जाकर उस सड़क को इस लिए रूकवा दिया ि कवह मेरे इलाके में बन रही थी।

उपमन्त्री (श्री राम प्रसाद): यह बिल्कुल झूठ है। मैनें कोई सड़क नहीं रूकवाई। बल्किी मैने चीफ इंजीनियर को पूछा भी तो उन्होने जवाब दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं

श्री राम प्रकाशः यह, जानाब झूठ बोलता है। वह सड़क बंद पड़ी है।

उपमंत्रीः जनाब यह झूठ बोल रहा है।

श्री राम प्रकाशः शट अप, सिट डाउन बगर।

सिंचाई मंत्रीः जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, या तो यह शब्द वापस करवाइए वरना इस तरफ से भी जवाब दिया जाएगा और इससे बढ़ कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री रमा प्रकाश जी अपने शब्द वापस लिजिए।

श्री दया कृष्णः जनाब, डिप्टी मिनिस्टर ने इस तरह से प्वायंट आफ आर्डर उठाया कि उन्होने प्रोबोक कर दिय।

श्री उपाध्यक्षः राम प्रकाश जी, इस तरह से हाउस की डिग्निटी खराब नहीं होने दी जाएगी। आप अपने शब्द वापिस लें

श्री राम प्रकाशः मैनें तो वापिस ले लिए लेकिन आप इनके मुंह में भी तो लगाम लगाएं। जनाब मैने यही का था ि कवह सड़क बन्द हो गई और यह हकीकत हैं जनाब मै यही इस सरकार से और इसके मिनिस्टरों से निवेदन करना चाहता हूं कि किन्हीं जजबात में आकर जो डिवैल्पमैंट के काम जहां भी हो रहे है वह बन्द नहीं किए जाने चाहिएं। आप ने देख कि जब हिनदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो सारा हिन्दूस्तान एक हुआ और आपस में पूरी कोआप्रेशन से लड़ाई लड़ी और मामयाबी हासिल की। मैंभी इनहे पूरा यकीन दिलाना चाहिमा हूं कि अगर हरियाण की बेहतरी की बात यह सोचेंगे तारे मैं पूरा पूरा इनके साथ कोआप्रेट करंगा और राम प्रकाश इस प्रदेश की डिवैल्पमेंट के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दें

(Mr. Speaker occupied the Chair)

ज्नाब स्पीकर साहिब इस गवर्नमैंट का हाल यह है कि एक आदमी जो राजी है उसको इतना खिलाते है ि कवह खा नहीं सकता अैर दूसरी और जो भूखा है उसको इतना भूखा रखते है ि कवह मर ही जाए। ऐसे कारमों से प्रदेश नहीं बना करता।

मैं स्कूलों के अपग्रेडेशन के बारे में बतलाना चाहता हूं कि एक एक तहसील में 11–11, 12–12, स्कूल अपग्रेड किए मगर

हमारे यहां के लिए 112 मेंसे एक का भी नम्बर नहीं आया। यह इस गवर्नमैंट का सौतेली मां का सलूक है जो हमारे इलाके के साथ हो रहा हौ। मै अपने वित्त मंत्री जिनक लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और राओ साहिब से जो यहां नहीं है निवेदन करूंगा कि इलाके के बेसिज पर किसी भी कांस्टीच्युएंसी के साथ चाहे वह किसी मेम्बर से ताल्लुक रखती हो, सौतेली मां का सलूक नहीं होना चाहिए। हमारे यहां के स्कूल भी अपग्रेह हो सकते थे लेकिन अफसोस है कि एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया। यहां वजीर तालीम इस वक्त नहीं है–– जब यहां आऐंगे तो बतलाऊंगा। अब में कुछ मैउिकल हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। गवर्नमैंट ने 100 नई आयुर्वेदिक डिस्पैंसरीज खोलने का एलान किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि यह वहां खली जानी चाहिएं जहां पर पहले डिस्पैंसरीज नहीं है। मरे इलाके में मंगलौर और धनैरा वगैरह जो जगहें है वहां पर न कोई सड़क है न की डिस्पैंसरी है। इस कलए उनक ा ख्याल रखा जाए। शोडूल्ड कास्ट्स के लिए सरकार ने जो रूपए का प्रोवीजन किया है मै उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन अगर उस रूपए को खर्च नहीं किया जाता तो उसका कोई फायदा नही ंहम ने देखा है कि मार्च से अब तक के लिए जो बजट पास किया था उस में चौबीस लाख रूपया हरिजनों के लिए रखा था। लेकिन अफसोस की बात है कि उस में से अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। मैं सरकार से रिक्वैस्अ करूंगा ि कइस रकम को हरिजनों के उपर खर्च किया जाए जो आप ने मंजूर कर रखी है।

Mr. Speaker: Please resume your seat now.

श्री राम प्रकाशः स्पीकर साहिब, मुझे आप पांच मिनट और दे दें अब मै फ्लड के बारे में अर्ज करूंगां मेरे भाइयों ने काह कि पंद्रह दिन के बाद फ्लड शुरू हो जाएंगे। स्जीकर साहिब, सारे हरियाणे को फलड से बचाने के लिए मै अपनी गवर्नमैंट को सजेशन दूंगा कि मेरे हलके में मारण्डा, टांगर, जांतांग और दो और नदियां है। अगर उनके ऊपर बन्ध बांध दिय जाऐ तो सारी प्राब्लम हल हो जाएगी और जो हर साल आप करोड़ो रूप्ए की रकम रिलीफ के लिए देते है वह भी बच जाएगी। खिजराबाद के उस पास जोरों की फसल बहूत होती है वहां पर अगर गत्ता मिल लगा दी जाए जाए को काफी फायदा हो सकता है। मै। अपनी सरकार को यकीन दिलाता हूं कि सरकार जो भी भलाई के काम करेगी हम अपनी तरफ से पूरी कोआप्रेशन देंगे लेकिन अगर हमारे साथ सौतेली मां का सलूक किया जाएगा तो वह बरदाश्त नीं करेंगें।

स्पीकर साहिब, देहातें में जो मुजारे है उन से जमीनें छूड़ाने के लिए लैंडलार्ड्ज उनक ऊपर झूठे दावे कर देतो है कि इन्होने हमें बटाई नहीं दी, क्योंकि बटाई लेते वक्त उन्हे कोई रसीद वगैरह जमींदार लोग नहीं देतें तो नतीजा यह होता है कि बेचारे गरीब मुजारों के खिलाफ डिगरी हो जाती है और उन्हे बेदखल कर दिया जाता है। मै निवेदन करूंगा कि अगर मुजारे के खिलाफ कहीं बटाई वगैरा का दावा किया जाए तो सरपंच या गांव

के किसी मुअजिज आदमी की गवाही पर उको खारिज कर दिया जाना चाहिएं अगर आप ने अनाज की पैदावार बढ़ानी है तो आप को मुजारेां को प्रोटैक्शन लाजमी तैर पर देनी चाहिए। बस इतना कह कर मै आप का धन्यवाद करता हूं।

चौधरी जगदीश चंद्र (शाहाबाद) : स्पीकर साहिब, बजट पर हस हो रही है। बहूत सी बातों में कांग्रेस और जन संघ के नाम से चुहलबबाजी होती रहीं इस में मै नहीं जाना चाहता। मै एक दो बातें पहले इस बजट पर कहूंगा। मेरे ख्याल में महंगाई का सब से बड़ असर जो सूबे में है उसका इस स्टेट के बजट पर भी असर है। रोजाना कमचारियों की मांग आती है कि हमारा डी. ए. बढ़ओ, कहीं कालेज और स्कूल टीचर पैसे मांगते है। तो सरकार के सामन इस तरह की कई प्रालम्ज पेश आ रही है। और सरकार मेरे ख्याल में मुश्किल में फंसी हुई है। इस लिए अगर इस प्राब्लम का कोई परमानैंट हल न सोचा गया तो यह सरकार या कोई और सरकार भी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि आप कहां तक ही.ए. और ग्रेड दे सकते है, पैसे कहीं दत से तो गिरेंगे नहीं। पेसे लैने का सरकार के पस सिर्फ एक ही तरीका है और वह है टैक्सिज लगाने का। ऐसे हालात में मै सरकार की बुराई नहीं करता क्योंकि यह तकलीफ में फंसे हुए है। इनके पास सिवाय टैक्स लगाने के पैसे लेने का और कोई तरीका नहीं है। अब सवाल यह है कि मंहगाई क्यों है और यह किस तरह दूर हो। पहले हमें इस के कारण सोया चाहिए। मेरा ख्याल है भाव ज्यादा

होने का यह कारण नहीं है कि हमारे यहां किसी किस्म की कमी है। यह गलत बात है कि हमारे यहां कोई कमी है। मैं सबूत पेश करता हूं इस बात का। गवर्नर साहिब के भाषण के सफा छः पर लिख हुआ है '' गो दो साल से सूबे के एन्दर बारिश नहीं हुई जिस की वजह से मारू फसले तबाह हूई है फिर भी पैदावार में दस प्रतिशत का इजाफा हुआ है'' इससे पिछले भाषण में और बजट स्पीचों में भी अगर आप देखें तो साल दर साल इजाफा दिखया जाता रहा है। और अर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की रिपोर्ट पढ़े तो वह आप को बहुत प्रोग्रैसिव मिलेगी। ऐग्रीकल्चर डिपाटैमैंट ने कभी भी अपनी रिपोर्ट में यह नहीं लिख कि अनाज की पैदावार कम हुई है। जब सब मानते है कि हमारे यहां अनाज की पैदावार साल दर साल बढ़ी है तो फिर कमी क्यों है। उसका यह भी कारण हो सकता था कि शायद सूबे से बाहिर न गया हो। लेकिन सूबे मे पाबन्दी थी इस लिए बाहिर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर रेट ज्यादा क्यों है?

श्री अध्यक्षः अब बच्चें ज्यादा तादाद से बढ़ रहे है।

चौधरी जगदीश चन्द्रः नहीं जी, बच्चों की निसत अनाज की पैदावार जयादा बड़ी है। अनाज काफी है इस मसले को हल करने का तरीका तो यह है कि सारेहिन्दुसतान के लिए पाबन्दी तोड दी जाए और वचापारियों को खुल दे दी जाए कि जाहं कोई मुनाफा हो वहां अपना माल ले जाएं लेकिन यह काम स्पीकर साहिब सैंट्रल सरकार के दखल से ही हो सकता है। मै

1948 की मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं। उन दिनों खांड की दिक्कत आज से भी ज्यादा थी। उस वक्त के मिनिसटर लेट री किदवई ने विविल सप्लाईज के अफसरान की मर्जी के खिलफ जिद करे कंट्रोल तोड़ दिया था तो एक दम बाजारों में खंड के ढेर लग गए थे। रिफयूजी लोग जितनी कीमत पर लाते थे उतनी कीमत पर ही बेच देते थे और खाली बोरियों के पैसे बचा लेते थे। तो इस तरह कीमतें एक दम नीचे आ गई थीं। तो स्पीकर साहिब जब सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक पैदावार बढ़ी है और सूबे से बाहिर भी नहीं जाती तो कमी क्यों पेश आ रहीं है। उस के जिम्मदार जखीर अंदोज हे। जब किसान अपनी प्रोड्यूस मण्डियों में लाता है तो वहां से वह बड़े बड़े सेठो के कोठों मे चली जाती है। फिर मार्किट में सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाइ कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो महंगाई बढ़ जाती है। मैं बढ़ती हुई महंगाई की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं सारे सूबे में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सब से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि मंहगाई क्यों बढ़ी । जो बड़े बड़े सरमायेदार है उन्होने अनाज के जखीरे बना रखे है। अगर यह सरकार कोई दिलेरी का काम करना चाहती तो उन जखीरेदरों को पकड़े और उन्हे उचित सजा दे, लेकिन ऐसा काम सरकार नहीं करती। जखीरेदारों को पकड़ कर महंगाई का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। संयुक्त पंजाब में गवर्नर श्री धर्मवीर को इस के बारे में कुछ करने का साहस हुआ था, उन्होने बड़े सराहनीय कदम उठाये थे लेकिन ब्लैक मार्किटंग करने वाले बड़े होशियार

निकले। उन्होने श्री धर्मवीर का कदम कामयाब नहीं होने दिया और सैंट्रल गवर्नमै।ट साहिब को अपने केस वापिस लेने पड़ें यह बात सही है कि जखरीरेबाजी के कारण ही यह मंहगाई हुई है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए अैर जखीरेअंदाजी का किला तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिये। जब तक यह काम पूरा नहीं होगा सरकार अपने कमचारियों का खर्चा बढ़ाकर भी सन्तोष नहीं कर पायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार दलेरी के साथ जखरीबाजी का को खत्म करे। जखीरेबाजी का ज्यादातर जोर शहरों में है। मेरे जनसंघी भाइयों का इन में ज्यादा हाथ होता है। चूंकि जखीरेबाजों का जोर शहरों में ज्यादा होता है तो जब कोई जखीरेदार पकड़ा जाता है तो जनसंघी भाई सरकार के पास उन्प्हें छुडवाने के लिए आ जाते है और उन्हे सजा नहीं मिल पाती। इसलिए जनसंघी भाई जो कि मिनिस्ट्री के नजदीक है, उन्हें चाहिए कि दिलेरी से काम लें।

इसके अलाता इस काम को सफल बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के बिना काम नहीं चलेगा। जो बड़े बड़े सैक्रेटरी है ये आप को काम नहीं दे सकते। पिछले दिनों सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डी.ए. बढाने के सम्बन्ध में यह बयान दे दिया कि जिसका खर्च नहीं चलता वह किसी दूसरे सूबे मे चला जाए। यह ठीक है– जो कबिल आदमी है वे दूसरी जगह जाने लगेंगे अगर उन्हे पूरी सहूलतें न मिली। लेकिन मै एक बात जरूर कहूंगा कि आप यह न भूले कि सरकारी कर्मचारियों के बिना क्या

आपका काम चल सकेगा? जो अपने काम में माहिर है अगर वे कहीं दूसरी जगह चले गये तो आप फेल हो जाएंगें मेरा ख्याल है कि आप जल्दी ही फेल हो रहे है।

दूसरी बात मै बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो कि आपने टैक्स लगाये है। इन टैक्सों के अलावा अगर उधर टैक्स लगा दें जिससे जींदारों पर कोई बोझ नहीं पड़ता तो मेरा ख्याल है सरकार को अच्दी आमदनी हो सकती है और जनता में भी कोई रोष नहीं होगा। जैसे हरियाणा प्रांत में रोहतक में पशु बहुत होता है और यहां से ाारी तादाद में पशु बाहिर भेजा जाता है। अगर बाहिर जाने वाले पशु पर पांच रूपये टैक्स लगा दे ंतो बाहिर से पैसा आने लगेगा। अगर ऐसा टैक्स लगाएंगे तो आप की ऐनिमल हसबैंउरी का खर्च इससे ही पूरा हो सकता है। इस तरह से गरीब लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार का काम भी चल पड़ेा। ऐनिमल हसबैंडरी में हजारों रूप्यों की मशीनें रखी हुई है और इन मशीनों से अच्छे सांड पैदा करने में हम दूसरे मुल्कों की नकल करते है जबकि हमारे रोहतक के सांड सब जगह मशहूर है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की नकल करें और हजारों–लाखों रूपया ऐसी स्कीमों पर बरबाद करें। इसलिए मै सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसी मशीने फार्मो से हटा दी जानी चाहिए जिन पर देश का रूप्या फिजूल में खर्च होता है।

तीसरी बात मै बलाक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यह गवर्नमैंट आफ इंडिया से फाइनेस्ड होता है लेकिन मैं

समझता हूं कि यह आजकल बिल्कुल फेल हो चुका है। यह बिल्कुल वाहियात चीज है। इन में कोई डिवैल्पमैंट का काम नहीं होता। हमारे जिला में शाहबाद ब्लाक हैं वहां दफ्तर भी है हर तरीके से डिवैल्पमेंट हुई है और म्युनिस्पिल एरिया में भी डिवैल्पमैंट हुई है लेकिन यह उसको ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। इसी तरह नीलोखेड़ी और कैथल वगैरह ब्लाक है। देहातों में बड़े बड़े गांव है उन में ब्लाक्स के कर्मचारी मिक्सअप ही नहीं होते। बी.डी.ओं को तो कोई जानता ही नहीं, ग्राम सेवक कभी कभी दौरे करते रहते हैं। इसलिए मैं दरखास्त करता हूं कि ब्लाक का महकमा बिल्कुल वाहियात है। यह फेल हो चुका है। (घंटी)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहिब, आपका टाईम हो गया है।

चौधरी जगदीश चन्द्रः स्पीकर साहिब मै अभी खत्म करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ब्लाक का जो सिस्टम है वह तहसीलदार के सुप्रर्द किया जाए ताकि जो फजूल खर्च है वह बच जाएं टाईम हो गया है इसलिए मै आपके सामने कुछ सुझाव रखूंगा।

यह जा आप प्लैन्ज बनाते है उन में सब स्कीमें को छोड़ कर तीन स्कीमें होनी चाहिएं– सब से पहले एग्रीकल्चरकी तरक्की के स्कीम हो जिससे हमें खाने के लिय`रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है। दूसरी स्कीम सड़को की तरक्की के लिए हो जिससे लोग बिजनैस बगैरा कर सकें और तीसरी स्कीम

ऐजुकेशन की होनी चाहिए। ऐजुकेशन लड़के और लड़कियों दोनो को प्रापर दी जानी चाहिए। हरियाणा प्रांत गर्ल्ज एजुकेशन के लिहाज से निल है। मैने स्कूलों में देखा कि दो दो बजे जब बस का टाईमा देख बच्चे स्कूलो से उठकर आ जाते है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इन तीनों स्कीमों की तरफ सरकार फौरी तौर पर ध्यान दें फजूल की चीजों को एक तरफ छोड़ कर मुख्य पहलुओं की तरफ ध्यान दें (एक मेम्बर की तरफ) आप मन में बड़े खुश हो रहे हैं और अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे है। बजट ऐसा ही हुआ करता है। सब गवर्नमैंट्स के बजट ऐसे ही होते हैं अगर आप सीरियसली सोंचे तो फजूल चीजों को छोड़ दें और जो अच्दी चीजे है उन्हे ले लें।

(6.00 P.M.)

श्री केसरा राम (डबवाली, एस.सी): स्पीकर साहिब, मैं आप का मशकूर हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है। आज बजट पर चर्चा हो रही है.....

एक आवाजः कोई शेर ही पढ़ दे।

श्री केसरा रामः मन्जरे तस्वीर दरदें दिल मिटा सकता नहीं।

आईना पानी तो रखता है पानी पिला सकता नहीं।

एक दो बातें देख कर मुझे बड़ा दूख हुआ है। आज देश में अन्न की बड़ी भारी कमी है लेकिन मुझे दूख के साथ कहना पड़ता है कि मै इन को पिछले 15 साल से अन्न की पैदावार बढ़ाने के बारे में तजवीजें देता आ रहा हूं मगर यह गौर नहीं करतें दरअसल यह ला कि किताब पढ़े है अल्ला की किताब नहीं पढ़े है। ला से तो जेब कतरा बनता है और वकील बन कर जेबें कतरनी शुरू कर देते है वह भी किसान की जो अन्न पैदा करता है। (विघ्न) मै कहता हूं कि ला से कुछ नहीं बनेगा। अगर रोटी खानी है तो ला की बजाए अल्ला की किताब पढ़ो। यह अन्न न प्रभाकर पैदा कर सकता है न वकील और अगर अन्न कोई पैदा कर सकता है तो वह दलीप सिंह और केसरा राम पैदा कर सकता है। बच्चों के कान पकड़ कर पैसे लेने वाला क्या अन्न पैदा करेगा। एक बात का मुझे बड़ दूख हुआ कि अन्न पैदा कने वाले किसान पर टैक्स लगा या बढ़ा दिया। स्पीकर साहिब, आप भी इस तबका से ताल्लुक रखते है और उनकी सारी हालत को जानते है। किसान के तो पहले ही दसों दुश्मान कुदरत की तरफ से है। सब से पहले चुहा आता है जब किसान बोता है। उसके बाद जब फसल मुंह को आती है तो बीसियों किस्म के खतरे टिडियां सुडिंया आती है फिर हवा आती है खुश्की आती है और उसके बाद पटवारी आता है।(हंसी) यह भी एक बीमारी है जो किसान को लगी हुई हैं। मै अर्ज करता हूं कि किसान जिस देश का कमजोर है वह देश भी कमजोर ही रहता है मजबूत नहीं हो सकता। किसान को यह नह समझो ि कवह देहाती है लेकिन याद रखो

कि जब तक किसान ऊंचा नहीं उठेगा तब तक यह ला वाले भी भटकते फिरेंगे, खाने को नहीं मिलेगा। वह तो ब्लैक कर लेते है मंगल सैन जी के ट्रक जाते है.....

श्री मंगल सैनः बेइमान आप होंगे, गल्तबयानी बंद करे और यह लफ्ज वापिस लें।

श्री केसर रामः चलो वापस ले लेता हूं। मै अर्ज कर रहा था कि अगर किसान ऊंचा उठेगा, उसे पानी, खाद बीज मिलेगा तभी वह मिट्टी से मिट्टी बनकर दाना पैदा करके आप के खाने को लाएगा और अनाज मंडी में आएगा लेकिन आज उस अनाज पेदा करने वाले किसान पर 14 किस्म के टैक्स है, मालिया है, बैटरमैंट टैक्स है और फिर खुश हैसियती टैक्स है। उसके बाद फिर उस गरीब पर कामर्शियल क्रापस टैक्स ठोका हुआ है। अब कहते हे कि यू.पी. के तर्ज पर टैकस लगाएंगे जिस बे बारे में भाई राम पाल जी ने बता दिया है और किसी को कोई पता नहीं कि यू.पी में क्या आफत है जो हम पर लादी जानी है। मै इन से कहता हूं कि अगर हरियाणा को खुशहाल बनाना चाहते हे तो किसान को खुशहाल बनाओ लेकिन एक तरफ तो आप किसान को मदद देने की बात करते है और दूसरी तरफ उस पर टैक्सों का इतना बोझ लाद रहें हे कि उसकी कमर टूट गई और अ बवह चल भी नहीं सकता हैं। अगर उसकी मदद करनी है तो पानी दो, बजी और खाद सस्ते दो और यह बैटरमैंट लैवी खत्म करो। यह बैटरमैंट की भी अजीब बात हैं। बैटरमैंट और खुशहैसीती दोनो

एक ही चीजें है लेकिन दो नाम दे कर दो टैक्स लगा दिए है। 10 रूपया बैटयमैंट और पांच रूपया खुश हैसीयती टैक्स। इस बैटरमैंट की 1855 से ले कर 24 किस्तें भर दी है, अब तो खत्म करों। हर दफा इन से पूछते है कि भाई हमें इनक ा हिसाब तो समझा दो लेकिन शहर वालों ने हमारी बहींया ही छुपा ली है और कोई हिसाब किताब नहीं करते। मै आप से कहता हूं कि अगर किसान की अनाज पैदा करने की ताकत न रही तो यह अन्न की कमी कौन पूरी करेगा और यह महंगाई कैसे दूर होगी? इस कमी को न डाक्टर साहिब पूरा कर सकते है न कोई कारखानेदार कर सकता है और न ही कोई सरकारी मशीनरी कर सकती है। यह अनाज तो किसान के खेत में ही पैदा होगां इस लिए मैं अर्ज करता हूं कि खेत में काम करने वाले की होसलाअफजाई करें अगर आप ने देश की भूख मिटानी हैं। और आप नए नए टैक्स लगा कर उसकी कमर न तोड़े। आप इन्तकामी भावना से काम न करं जिस तरह कि आप ने इस 21 मई के चुनाव के बाद कई लोगों के मोघे बन्द कर दिए और खल बंद कर दिए और कहीं कुछ और कर दिया। इस तरह से इस प्रांत की डिवैल्पमैंट नहीं होगी। अगर यही हालत रही तो अनाज नहीं मिलेगा जिसक सबूत आज मिल रहा हैं कि चने का भाव 105 रूपया कविंटल है और गंदम 110 रूपए मिल रही है। इस हालत में क्या खाएगा मजदूर और कर्मचारी जब पैदा करने वाले के पास ही अनाज नहीं है। जहां तक पानी देने की बात है हरियाणा मे पानी बहूत है यह मै जानता हूं और मैने पता किया है। पांच नदियां हमारे हरियाणा में

मारकंडा,टांगरी,घागरा बगैरा है जिनका पानी स्कीमें बना कर आप आबपाशी के काम ला सकते है। हर साल घग्गर आप के खनौरी के इलाके में तूफान मचाती है। आप अगर इस पानी को कंट्रोल करके किसानो को दें और पूरे जिला हिसार को पानी देदें तो में कहता हूं हरियाणा के अन्दर अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। तालीम के बारे मै जैसा की चौधरी साहिब ने भी कहा आज बस बी.ए. पास अगर उसके पास आटा भी है तो रेाटी बना कर खा नीं सकता बाकी बातें तो छोड़ों। इस लिए मै कहता हूं कि जब तक टैक्निकल तालीम नहीं दी जाएगी तब तक यह देश उंचा नहीं उठेगा तालीम के बारे में मै ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन इन दिनों मे जो हालत हो रही जहे उस से लोग बहुत दूखी हैं जो सकूल जिछली सरकार ने अपग्रेड किएथे जो छः छः हजार वाली आबादी वाले गांव में थे जिनकी इमारते शानदार थी उन्हे कैंसल कर दिया हैं मेरे हल्का में तीन स्कूल अपग्रेड किए गए थे लेकिन तीनों कैंसल कर दिए है। यह है इन की डिवैलपमैंट जो यह कर रहे है। मेरे हलका में गंगा गांव काफी बड़ा कसा हैं। वहां मिउल से हाई स्कूल किया गया लेकिन इस सरकार ने आते ही पता नहीं इन्तकामी भावना से उसे कैंसल कर दिया और उसे मिडल ही रहने दिया और उसकी बजाए कहीं देहली के पास जा कर हाई स्कूल बना दिय। एक दो मिडल स्कूल ऐसे थे जाहं सब कुछ तैयार था और स्टाफ भी जाने को तैयार था लेकिन यह बाई–इलैक्शन का वह तूफान उठा ि कवह स्कूल भी कैंसल कर दिया। सरसा के इलाका में खास तौर पर बहूत कम स्कूल है।

वहां की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खाली हरफी तालीम से ही काम नहीं चलेंग, टैक्निक्ल तालीम की तरफ ध्यान दिया जाए।

पानी का महकमा हमारे एक नौजवान के पास है पढ़े लिखे आदमी है, कांग्रेस जानती हैं। लेकिन इस वक्त पानी के कंट्रोल और तकसीम का जो इन्तजाम है इससे किसान बहुत दूखी है। एक नाके के लिए चार चार चक्कर लगााने पड़ते है। सरकारी कर्मचारी जो है वह इस बात की और पूरा ध्यान नहीं देता और खस करके पटवारी तो किसान को उसी तरह से तंग करते है। जैसे टिड्डी और चूहे। वह तख्मीने की पैदावार को गलत दिखलाता है और सरकार को धोखे मे रखता हे। हरेक आदमी जानता है कि पिछले दो तीन सालों से खुश्कसाली चली आ रही है परन्तु पता नहीं कि पटवारी पुख्ता पेदावार कैसे दिखलाता है। जब पुख्ता पैदावार होगी तो मंडियों में अनाज समायेगा नहीं आज तो हालत यह है कि जो होशियार आदमी है वह पंजाब से या राजस्थान से ट्रक भर भर कर मंडियों में ला रहा है वरना हमारे हरियाण के अन्दर खुश्कसाली है और इसकी वजह से यहां अन्न की कमी हैं। अगर नहरी पानी किसान को मुहैया कर दिया जाए तो मै दावे से कहता हूं कि हरियाणा का किसान आज यहां जो भूख है उसको मिटा सकता है।

स्पीकर साहिब चौधरी रिजक राम जी ने जो भय प्रकट किया है कि हमारी सरकार की यह बातें कहीं दीवार की तस्ती बन

कर ही न रह जाएं इससे में इत्तफाक करता हूं क्योंकि दीवार की तस्वीर से किसी की भलाई नहीं हो सकती। हरिजनों के लिए पैसा देने की स्कीम की नींव सरदार प्रताप सिंह कैरो ने रखी थी। काफी पैसा वे दिया करते थे परन्तु घटते घटते वह काफी कम हो गया था। खैर इस साल में 70 लाख रूपया मिला है इस बजट में भी इसक जिक्र है। मै, स्पीकर सहिब सरकर से अर्ज करूंगा कि वह इस स्कीम को अमली जामा पहना कर कामयाब बनाएं जिससे कि हरिजन लोगो जो कि बैकवर्ड और सदियों से पिछड़े हुए गरीब लोग है उनको रोजगार मिले।

अन्त में मै, स्पीकर साहिब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए, कयोंकि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए काफी समय दिया, इरीगेशन मिनिस्टर साहिब से अर्ज करना चाहता हूं कि वे किसान को बैटरमैंट टैक्स के बारे में तसल्ली दें आज हरियाणा का किसान बड़ा बचैन है। सरकार को चाहिए कि वह किसान को इस भार से बचाए ताकि हरियाणा का किसान हौसले से खेती करके हरियाणा की वर्तमान भूख को मिटा सके।

श्री बंसी लाल (तोशाम): स्पीकर साहिब, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे मालूम होता है कि यह बजट जनसंघ पार्टी से प्रभावि होकर तैयार किया गया है। कहने को तो हमारी आज की सरकार देहातियों की सरकार है मगर जब इस के ऐक्शन देखे जाते है तो ऐसा महसूस होता है कि यह प्योश्रली जनसंघ की सरकार है। सरकार ने जो पांच एकड़ जमीन

पर लैंड रैवेन्यू माफ किया उससे पूरे हरियाणा के देहातियों को सिर्फ 14 लाख का फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो टैक्सिज गरीब किसान के ऊपर लगाऐ गये है चार करोड़ रूपये से भी अधिक होंगे। वाटर रेट जो लगाया गया है उससे 212 लाख रूपया वसूल होगा और रजिस्ट्रशन वगैरहाजी इम्मूवेबल प्रोपर्टी की खरीदो फरोख्त पर बढ़ाया गया है प्राप्त होगी उससे सरकार को 25 लाख रूपये की आधिक आमदनी होगी। क्योंकि अधिकतर एग्रकल्चरल लैंड बेची जाती है, उसकी खरीदफरोक्त होती है इसलिए यह भी टैक्स किसान के ऊपर है। लैंड रैवेन्यू के 50 प्रतिशत सरचार्ज से 46 लाख रूपये को मिलेंगे और पैसेंजर टैक्स जो 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया है उससे 80 लाख रूपया अधिक वसूल होगा। तो इन सब टैक्सों को मिलाकर सरकार को 402 लाख रूपये अधिक वसूल होंगे। एक तरफ तो अध्यक्ष महोदय सरकार ने 14 लाख रूपये की राहत दी लेकिन दूसरी तरफ 402 लाख रूपये के टैक्स लगाए है। इससे साफ जाहिर है कि यह सराकर देहातियों की नहीं बल्कि जनसंघ की सरकार है। 25 लाख रूपया ट्यूबवैल्ज और 20 लाख रूपया लिंक और विलेज रोडज बनाने के लिए जो प्रोवाईड किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर मैं समझता हूं कि टयूबवैल्ज के लिए 25 लाख रूपया जो रखा गया है वह बहूत कम है। 25 लाख रूपये मे काम चलने वाला नहीं। अच्छा होता यदि वित्त मंत्री इस रूपये की बजाय एक करोड़ रूपया इस मद में रखते। मुझे आशा

है कि मेरी इस बात को ध्यान में रख कर सरकार इस प्रोवीजन को बदलेगी जिससे कि अधिक टयूबवैल्ज लग सकें।

वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में यह भी बताया कि एक करोड़ रूपया किसानों को उत्तम बीज और फर्टिलाइजर आदि खरीदने के लिए लोन देने के लिए रख है। यह बहूत अच्दी बात है। इस लोन में ट्रेक्टर खरीदने का लोन भी शामिल है। मगर यह लोन जिला परिषद् की मारफत दिया जाता है जो कि एक पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन है। जो आदमी जिला परिषद् की मारफत दिया जाता है जो कि एक पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन है। जो आदमी जिला परिषद् के चेयरमैन तक एप्रोच कर सकता है या जो उसकी पार्टी के आदमी होते है उन को कर्जा मिल जाता है लेकिन सही आदमी को नहीं मिल पाता। तो,स्पीकर साहिब, आप के जरिए मै वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह रूप्या डिप्टी कमिश्नर या एस.डी.ओ. की मारफत कतसीम किया जाए ताकि ठीक ढंग से डिस्ट्रिब्यूशन हो सके। यह बात मै ट्रैक्टर खरीदने के लोन को बाबत कह रहा हूं।

इस के बाद वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया कि सतलुज–ब्यास लिंक तैयार होने के बाद पानी आधिक मिल सकेगा और आज जो हरियाणा की कुल खेती करने वाली भूमि का 31 प्रतिशत हिस्सा से रौब होता है उसमें बढ़ौतरी होगी। मगर वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जब अधिक पानी आएगा तो जिन इलाकों में पानी मिल रहा हे उन को और अधिक मिलेगा

और महेन्द्रगढ़ जिले को भी कुछ पानी मिलेगा। अच्छी बात है कि उसको पानी मिलना चाहिए। मगर जिस वक्त सरकार कोई स्कीम तैयार करती है उस वक्त भिवानी तहसील को हमेशा इगनोर किया जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए मै प्रार्थना करता हूं कि भिवानी तहसील को भी इस में शामिल किया जाए।

वित्त मंत्री जी ने यह भी बताया कि 10 लाख रूप्या गुड़गांव और रोहतक के किसानों की ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाएगा। मै समझ नहीं पाया कि यह रूप्या इन जिलों में ही क्यों खर्च होगा। क्या बाकी के जिले ऐसे है जहां ट्रेनिंग की जरूरत नहीं।

राज्स्व मन्त्रीः ये तो सैन्टर हैं।

श्री बंसी लालः यदि सैन्टर है तब तो ठीक है लेकिन वित्त मंत्री जी ने सिर्फ गुड़गांव और रोहतक ही कहा है और इस बात को साफ करके नहीं लिखा है कि वे सैन्टर होंगे और बाकी जिलों में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कहते है कि सब जिलों में दी जाएगी तो मैं इसका स्वागत करता हूं।

वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि सरकार कुछ रिंगज खरीदना चाहती है जिससे ट्यूबवैल्ज लगाने के लिए यह देखा जा सके कि पानी अच्छा है यह बुरा है। तो, स्पीकर साहिब आपके जरिए मै प्रार्थना करूंगा कि ये रिंगज जितना जल्दी हो

सकें उतना जल्दी खरीदे जाएं ताकि आबपाशी का पूरी स्टेट को फायदा हो सके।

माइनर इरीगेशन के लिए चार करोड़ रूपया करनाल और गुड़गांव के लोगों को कर्जा देने के लिए रखा गया है। यहां भी, अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी है कि बाकी जिले क्यों छोड़ दिए गए, जैसे हिसार है, महेन्द्रगढ है और जींद हैं । मै समझता हूं कि यह कर्जा हर जिले को आबादी के लिहाज से हिस्सा के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से देने की तजवीज करनी चाहिए।

हमारे वित्त मंत्री ने ऐजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का जिक्र किया। यह ठीक है मगर स्पीकर साहिब मै यह समझता हूं कि जब तक आज के ऐजूकेशन मंत्री रहेंगे उनके होते हए यह फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। उन्होने अभी तक जो स्कूलो की अपग्रेडिंग की है वह पोलिटिकल कन्सिड्रेशन पर की है। मिनिस्टर साहिब यहां मौजूद नहीं है, इसलिए मै चांद राम जी से कहूंगा कि वह उन्हे बतला दें जो कुछ मै कह रहा हूं। हालूवास एक गांव भिवानी तहसील में है। इस के दो हिस्से है एक तो भिवानी चुनाव क्षेत्र में है जिसको श्री प्रभाकर जी रिप्रजेंट करते है और दूसरा तोशाम है जिसे मै रिप्रैजेंट करता हूं। हालूबास मे जिस हिस्से को मैं रिप्रजेंट करता हूं वहां पर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग तैयार है। लड़को की तादाद भी अच्छी है। 20 बीघे जमीन भी गांव के लोगों ने छोड़ दी है, खेलने का मैदान भी वहां पर इस तरह से काफी बड़ा है और बहूत अच्दा है। दूसरी तरफ

भिवानी क्षेत्र में जो हिस्सा है वहां पर इमारत भी नहीं है, लड़को की जयादा वहां पर तादाद नहीं है न ही खेल कूद के लिए कोई मैदान है। लेकिन जो फैक्ट है वह मै आप के जरिए हाउस में रखना चाहता हूं कि मैने दरखास्त की थी कि मेरे हलके के स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए। मेरी दरक्षस्त मान भी ली गई थी लेकिन जब पोलिटिकल प्रैशर पड़ा तो अपग्रेडिंग उन्होनें भिवानी क्षेत्र के इलाके में जो स्कूल था इसकी कर दी और हमारा स्कूल वैसे का वैसे ही रह गयां हैरानगी की बात है कि जाहं न तो इमारत है न जमीन खेल कूद के लिए और न तादाद ही काफी वहां पर तो स्कूल अपग्रेड किया जाता है चाहे बेशक लड़के बाद में सर्दीगर्मी और बारिश के कोप के भाजन बनते रहेंगे, मगर जहां पूरी सहूलियत है वहां पर सिर्फ इसलिए कि पालिटिकल कन्सिड्रेशन है स्कूल मंजूर किया हुआ भी अपग्रेउ नहीं किया गया। इसलिए मै खुले रूप से यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा मिनिसटर के हाते हुए हम यह तरक्की नहीं कर सकते कि जो जैन साहिब ने ऐजुकेशनल फैसिलिटीज की बात बजट में कही है वह न्याय पूर्वक पूरी हो सके।

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीः आप ने बांकोड़ा गांव की बात नहीं कही।

श्री बंसी लालः मै ने उसके लिए भी दरखास्त की थी और लिखा था कि वहां पर भी आपग्रेड हो मगर बात नहीं सुनी गई। वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट सपीच में यह बात भी कही है

आपशन दे दी है। यह बड़ी अजीब बात है। हरियाणा में अगर इस तरह की आपशन की बात हिन्दी में नोटिंग करने के लिए कही जाती है, तो बड़े ताज्जुब की बात है। हां अगर इंगलिश स्पीकिंग वहां पर हिन्दी में आपशन की बात कहना शोभा नहीं देतां मै समझता हूं कि सराकरा अपनी पालिसी को रिवाईज करेगी और डपर के लैवल नीचे के लैवल तक सारा काम हिंदी में हो ऐसा हिदायत दे दी जाएगी।

आयुर्वेदिक डिस्पैंसरीज की बात वित्त मंत्री जी ने कही। मगर मैं यह कहना चाहता हू कि यह डिस्पैंसरीज मैरिट के हिसाब से खोली जानी चाहिएं।

ट्रांस्पोर्ट के द्वारा जो लाभ पिछले वर्ष हुआ है जैसा कि बजट स्पीच में दर्ज है कि नवम्बर 1966 से मार्च 1967 तक प्रति मास लाभ 4.49 लाख की औसत आमदनी हूई और अप्रैल, 67 में यह लाभ 8.6 लाख रूपए हो गया तथा मई 1967 में यही लाभ बढ़ कर 12 लाख हो गया। यह बड़ी खुशी की बात है, मगर यह और भी अच्छा होता कि वित्त मंत्री साथ के साथ यह भी ऐलान करते कि सारी बसों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। अगर वह ऐसा कर दे ंतो गरीब आदमियों को टैक्स से रिलीफ दिया जा सकता है। निवेद करता हूं कि इस पर हमारी सरकार गौर करें।

ड्रिंकिग वाटर सप्लाई के लिए 66 लाख रूपया रख जाना मैं समझता हूं कि बहूत ही कम है। भिवानी तहसील में, और

महेन्द्रगढ जिले में ऐसे भी गांव है जहां पर पानी 10, 10 मील से आता है। ताज्जुब होता है कि आज भी 20 साल हो गए लेकिन पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया। भिवानी तहसील के लिए तीन स्कीमों का काम सम्पूर्ण नहीं हुआ। मै सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और पानी की स्कीमों को पूरा करने के लिए 66 लाख से बढ़ कर ज्यादा रकम कर दें।

इसी तरह जब फैमिन रिलीफ का हैउ देखते है तो पता चलता है कि इस के लिए सिर्फ बीस लाख रूपया रखा गया है। पिछले साल भी भिवानी तहसील में अकाल पड़ा था और खर्च 30—40 लाख रूपया हुआ था। मगर आज भिवानी तहसील में कहत है, महेन्द्रगढ़ जिले में कहत है। यह बीस लाख रूप्या ना के बराबर है। इसकी राशि कम से कम दो करोड़ होनी चाहिए। आज भी भिवानी के लोगों की ऐसी हालत है कि मुश्किल से स बार खाना मिलता है। वह सरकार की तरफ देख रहे हे कि सरकार उनक ` लिए कुछ करेगी और उन्हें कुछ रोजी मिलेगी लेकिन अभी तक न तो सड़को का बनाना शुरू हुआ और न कुंडो वगैरह की कार्यवाही शुरू हुई जैसी कि कहत के दिनो में हाती हैं। मै समझता हूं कि सरकार की यह गफलत है जिसको कि जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। राशन की दुकानों पर राशन भी नहीं मिलता है।

Mr. Speaker: Wind up please.

श्री बंसी लालः बस जी मै खत्म ही करा हूं। महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले एम्पलाईज को 10 परसेंट अधिक अलाडंस दिया जाता है बनिस्बत और जगहों के इसका कारण यह है कि वह बैकवर्ड इलाका है मगर भिवानी तहसील में जाने वाले मुलाजिमों को कोई अलांउस नहीं दिया जाता जब कि वह उससे भी पिछड़ा हुआ इलाका हैं। उन्हे भी अलाउंस दिया जाना चाहिए।

अन्त में मै वित्त जी से और चीफ मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना करूंगा कि गरीब किसानों पर जो टैक्स लगाए है, उन टैक्स प्रोपोजल्ज को सरकार रिवाईज करे और ट्रांसपोर्ट को नैशनेलाइज करके खर्च को पूरा करे ताकि गरीब लोगों को भार से मुक्ति मिले। आपका बहूत धन्यवाद।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9 A.M. tomorrow (The Sabha then adjourned till 9 A.M. on Wednesday, the 14th June, 1967)

APPENDIX

To

HARYANA VIDHAN SAHA DEBATES, VOL.1 NO. 15
DATED 13TH JUNE 1967

Tenants ejected in the State

***269. Shri Ram Parkash:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of tenants ejected in the State, tehsil-wise, during the period from 1st January, 1966 to date together with the number of those who have been allotted land in lieu thereof?

Shri Chand Ram: A statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the total number of tenants ejected tehsil-wise during the period 1-1-66 to date.

S. No.	Name of District	Name of Tehsil	No. of tenants ejected	No. of tenants who have been allotted land
1	Hissar	Sirsa	391	352

		Fatehabad	308	308
		Hissar	143	139
		Hansi	89	83
		Bhiwani	51	43
		Total	982	925
2	Rohtak	Rohtak	125	46
		Sonepat	115	31
		Jhajjar	178	69
		Gohana	73	24
		Total	491	170
3	Karnal	Karnal	119	119
		Kaithal	77	77
		Panipat	136	133
		Thanesar	92	90
		Total	424	419
4	Ambala	Ambala	116	116
		Jagadhri	118	118
		Naraingarh	40	40
		Total	274	274

5	Gurgaon	Gurgaon Rewari Nuh Feroepore Jhirka Palwal Ballabgarh Total	92 51 120 68 208 36 575	25 41 64 5 72 11 218
6	Mohindergarh	Karnal Mohindergarh Dadri Total	8 18 7 33	1 9 6 16
7	Jind	Jind Narwana Total **Grand Total**	 **2,779**	 **2,022**